



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 अप्रैल, 2018 ई0 (चैत्र 24, 1940 शक सम्बत्) [संख्या-15

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	रु0 3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	171-198	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	247-291	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	—	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	103-105	975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप

22 फरवरी, 2018 ई०

संख्या 403/VII-2-18/41-M.S.M.E./2016-भारत सरकार द्वारा देश में स्टार्ट-अप के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से स्टार्ट-अप इण्डिया पहल की घोषणा की गई है। स्टार्ट-अप की पहचान, मान्यता आदि के संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-113, दिनांक 17.02.2016 निर्गत की गई है। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में इन्क्यूबेशन (Incubation) एवं स्टार्ट-अप क्षेत्र में पूँजी निवेश को बढ़ावा दिये जाने तथा राज्य के विभिन्न तकनीकी संस्थानों से प्रशिक्षित छात्रों को एक उद्यमी के रूप में विकसित किए जाने के उद्देश्य से शासन के सम्यक् विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-955/VII-2-17/41-एम०एस०एम०ई०/2016, दिनांक 29.06.2017 द्वारा लागू उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट-अप नीति-2017 को पूर्णतः प्रतिस्थापित करते हुए "उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट-अप नीति-2018" प्रख्यापित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

"उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट-अप नीति-2018"

1. दृष्टि :

उत्तराखण्ड में उद्यमशीलता की भावना को पोषित कर एक पारिस्थितिकीय तंत्र को बढ़ावा देकर राज्य को देश में स्टार्ट-अप के लिए सबसे उपयुक्त राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित करना है।

2. उद्देश्य :

नीति का उद्देश्य निम्नलिखित को प्राप्त करना है:-

1. उत्तराखण्ड में कम से कम 500 नए स्टार्ट-अप का विकास एवं पोषण।
2. इच्छुक एवं वर्तमान उद्यमियों के लिए निवेश की सुविधा प्रदान करना।
3. उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देकर वर्तमान नौकरी खोजने वाले रूझान से नौकरी देने वाले रूझान को बढ़ावा देना।

3. परिभाषा :

3.1. उपक्रम (एन्टिटी) :

एक कम्पनी (कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार), एक पंजीकृत साझेदारी फर्म (पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के तहत) या सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत)।

3.2. स्टार्ट-अप :

उत्तराखण्ड स्टार्ट-अप नीति के अन्तर्गत एक इकाई को "स्टार्ट-अप" माना जाएगा, यदि वह नीचे दी गई चार शर्तों को पूरा करेगी या यदि इकाई स्टार्ट-अप इण्डिया की पहल के तहत मान्यता प्राप्त है और नीचे चौथी शर्त को पूरा करती है:-

- (1) उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से सात वर्ष तक; यथापि, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के स्टार्ट-अप के मामले में, यह अवधि उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष तक होगी; और

- (2) निगमीकरण/पंजीकरण के बाद से यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका कारोबार ₹ 25 करोड़ से अधिक नहीं हुआ हो; और
- (3) पहले से ही मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनाई गई किसी संस्था (एन्टिटी) को 'स्टार्ट-अप' नहीं माना जाएगा।
- (4) उत्तराखण्ड में इसे निगमित/पंजीकृत किया गया हो अथवा कुल अर्ह कर्मचारियों की कम से कम 50 प्रतिशत संख्या उत्तराखण्ड से हो, जिसमें अनुबन्ध कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त क्रमांक सं0 1 से 3 में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले परिवर्तन/परिवर्द्धन उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू माने जायेंगे।

3.3. इनक्यूबेटर :

इनक्यूबेटर व्यावसायिक सहायता, संसाधनों और सेवाओं जैसे-भौतिक स्थान, पूँजी, प्रशिक्षण और सलाह कॉर्पोरेट और कानूनी सेवाओं सहित सामान्य सेवाओं और नेटवर्किंग अवसर प्रदान कर मापनीय व्यवसाय मॉडल विकसित करने में सहायता के लिए प्रारम्भिक चरणों के दौरान स्टार्ट-अप कम्पनियों का सहयोग करने वाला एक संगठन है।

केन्द्र या राज्य सरकार से वित्त पोषित या पंजीकृत इनक्यूबेशन को इस नीति के अन्तर्गत इनक्यूबेटर माना जायेगा। उदाहरण के लिए नीति आयोग के तहत अटल इंक्यूबेशन सेंटर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (टी0बी0आई0)।

1. इनक्यूबेटर को निम्न श्रेणियों में से किसी एक के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए:-

- (क) सोसायटी (सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत),
- (ख) धारा-8 कम्पनी (कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत),
- (ग) कम्पनी (कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत),
- (घ) सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत),
- (ङ) लोक चैरिटेबल ट्रस्ट (भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत)

2. इनक्यूबेटर को इंक्यूबेटीस के साथ क्रियाशील स्थिति में कम से कम 3 माह तक प्रत्यक्ष अथवा वर्चुअल रूप से सहायता करनी चाहिए।

3.4. एंजल इन्वेस्टर :

एंजल इन्वेस्टर आमतौर पर समृद्ध या उच्च निवल मूल्य के व्यक्ति हैं, जो स्टार्ट-अप अथवा उद्यमियों को शुरुआती या प्रारम्भिक वित्त पोषण प्रदान करते हैं। एंजल इन्वेस्टर प्रतिफल के रूप में कम्पनी में इक्विटी हिस्सेदारी या परिवर्तनीय ऋण के रूप में स्वामित्व प्राप्त करते हैं।

3.5. एंजल नेटवर्क :

एंजल नेटवर्क, एंजल इन्वेस्टर का एक समूह है, जो साथ-साथ निवेश करते हैं, पेशेवर रूप से प्रारम्भिक चरण के व्यवसाय के लिए फण्ड को प्रबन्धित करते हैं। एंजल समूह, सदस्यों के साथ संसाधनों और ज्ञान को साझा कर के उभरते हुए बाजारों में एकल निवेश के जोखिमों को कम कर सकते हैं।

3.6. नवोन्मेष :

किसी विचार या आविष्कार को एक वस्तु या सेवा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, जो मूल्य पैदा करती है, जिसके लिए ग्राहक भुगतान करेंगे। नवोन्मेष में संसाधनों से अधिक से अधिक या भिन्न मूल्यों को प्राप्त करने में जानकारी, कल्पना और पहल के आवेदन शामिल हैं।

3.7. विश्वविद्यालय :

केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अथवा ऐसी कोई भी संस्था जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो।

3.8. स्टार्ट-अप काउंसिल :

स्टार्ट-अप काउंसिल एक संस्था है, जिसे उत्तराखण्ड स्टार्ट-अप पहल पर नजर रखने और कार्यान्वित करने के लिए सरकारी और निजी पृष्ठभूमि से चयनित सदस्यों को सम्मिलित कर, गठित किया जायेगा। काउंसिल का गठन विभाग द्वारा अलग से किया जायेगा।

3.9. टास्क फोर्स :

आयुक्त उद्योग की अध्यक्षता में, उद्योग निदेशालय स्तर पर एक टास्क फोर्स गठित की जायेगी, जो स्टार्ट-अप काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त Startups/Incubators को नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों (₹ 10.00 लाख/प्रति लाभार्थी तक) को प्रदान करने हेतु अधिकृत होगी।

3.10. नोडल एजेंसी :

सभी श्रेणी के स्टार्ट-अप को प्रमाणित करने के लिए स्टार्ट-अप काउंसिल द्वारा अनुमोदित प्रतिष्ठित संस्थान/संगठन।

4. नीति अवधि :

उत्तराखण्ड की स्टार्ट-अप पॉलिसी अधिसूचना जारी होने की तिथि से 07 वर्षों तक अथवा अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी।

5. फोकस क्षेत्र :

पॉलिसी के लिए प्राथमिक फोकस सेक्टर निम्नलिखित हैं:-

1. यात्रा और पर्यटन,
2. खाद्य प्रसंस्करण और कृषि (उद्यान सहित),
3. आयुष,
4. शिक्षा,
5. स्वास्थ्य क्षेत्र (Healthcare),
6. जैव प्रौद्योगिकी,
7. फार्मास्यूटिकल्स।

उक्त सूची के अतिरिक्त समय-समय पर अन्य क्षेत्र, जो कि राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद् द्वारा अनुमोदित किए जायेंगे, भी योजना के अधीन पात्र होंगे।

6. लाभ/प्रोत्साहन :

6.1. स्टार्ट-अप :

स्टार्ट-अप काउंसिल द्वारा "स्टार्ट-अप" के रूप में मान्यता प्राप्त इकाई अग्रसारित लाभ/प्रोत्साहनों के लिए योग्य होगी:-

6.1.1. मासिक भत्ता :

स्टार्ट-अप काउंसिल द्वारा चुने गए सामान्य श्रेणी के स्टार्ट-अप को ₹ 10,000 तथा अनु0 जाति/अनु0जनजाति/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों को अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015 के अन्तर्गत वर्गीकृत श्रेणी 'ए' के जनपदों में स्टार्ट-अप व्यवसाय स्थापित करने पर मासिक भत्ता ₹ 15,000 देय होगा, जो अधिकतम एक वर्ष तक दिया जायेगा।

6.1.2. विपणन सहायता :

मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप द्वारा नवाचारी उत्पाद के विपणन/प्रचार-प्रसार पर ₹ 5.00 लाख तक की विपणन सहायता स्टार्ट-अप काउंसिल के अनुमोदन के पश्चात् देय होगी।

नीति के अन्तर्गत फोकस क्षेत्रों में अनु0जाति/अनु0 जनजाति/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों को अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015 के अन्तर्गत वर्गीकृत श्रेणी 'ए' के जनपदों में स्टार्ट-अप व्यवसाय स्थापित करने पर विपणन सहायता ₹ 7.5 लाख तक देय होगी। यह सहायता स्टार्ट-अप को एक बार देय होगी।

6.1.3. प्रतिपूर्ति/छूट :

पेटेंट (बौद्धिक सम्पदा)

स्टार्ट-अप पेटेंट शुल्क (फाइलिंग शुल्क, अटॉर्नी शुल्क, अन्वेषण शुल्क, रख-रखाव शुल्क सहित) की वास्तविक लागत की 100 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति के लिए अर्ह होंगे, यह प्रतिपूर्ति भारतीय पेटेंट की दशा में ₹ 1 लाख तक तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट की दशा में ₹ 5 लाख तक देय होगी, यह प्रतिपूर्ति 75 प्रतिशत आवेदन दाखिल करते समय तथा 25 प्रतिशत अभियोजन के समय देय होगी।

स्टॉम्प शुल्क :

स्टार्ट-अप परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप को लीज डीड/स्थान/भूमि क्रय करने पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015 के अन्तर्गत वर्गीकृत श्रेणियों के अनुसार स्टॉम्प शुल्क में छूट देय होगी।

राज्य माल एवं सेवा कर :

स्टार्ट-अप परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप को उत्तराखण्ड राज्य की संबंधित फर्म/इकाई द्वारा प्रदेश के भीतर उपभोक्ता (बी0 टू0 सी0) को माल की आपूर्ति पर अनुमन्य आई0टी0सी0 के समायोजन के पश्चात् जमा किए गए एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति बजट के माध्यम से की जायेगी।

6.1.4. अवसंरचनात्मक सहयोग :

इनक्यूबेटर तथा सामान्य सुविधा केन्द्रों की सूची उत्तराखण्ड स्टार्ट-अप पोर्टल पर उपलब्ध होगी, जिसे "रियल टाईम बेसिस" पर अद्यतन किया जायेगा।

इनक्यूबेशन स्पेस :

स्टार्ट-अप परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग स्टार्ट-अप को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर की अधिसूचित दरों से 25 प्रतिशत कम दर पर इनक्यूबेटर में स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।

6.1.5. आवश्यकता आधारित सहायता :

नए उत्पाद के विकास/वर्तमान उत्पाद में सुधार के लिए नवोन्मेष हेतु आवश्यक कच्चा माल/घटक तथा अन्य सम्बन्धित उपकरणों के लिए स्टार्ट-अप परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप को ₹ 5 लाख तक की आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान की जाएगी।

यह सहायता कच्चा माल/उपकरण की नवोन्मेष के लिए आवश्यकता होने पर ही देय होगी तथा स्टार्ट-अप परिषद् के अनुमोदन पर निर्भर करेगी।

6.2. इन्क्यूबेटर्स :

स्टार्ट-अप काउंसिल द्वारा "इन्क्यूबेटर" के रूप में मान्यता प्राप्त इकाई निम्नलिखित लाभ/प्रोत्साहनों का लाभ लेने के लिए योग्य होगी।

6.2.1. पूँजीगत सहायता :

इन्क्यूबेटर्स को पूँजीगत लागत का पचास प्रतिशत अधिकतम ₹ 1 करोड़ तक पूँजीगत सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता एक बार देय होगी तथा पूँजीगत लागत में भूमि तथा भवन की लागत की गणना नहीं की जाएगी। यह सहायता नए इन्क्यूबेटर स्थापित करने पर अथवा स्थापित इन्क्यूबेटर को क्षमता बढ़ाने के लिए दी जाएगी।

6.2.2. चालू खर्च हेतु सहायता :

स्टार्ट-अप परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर्स को 3 साल की अवधि के लिए संचालन और प्रबन्धन खर्च के रूप में प्रतिवर्ष ₹ 2 लाख तक की सहायता देय होगी।

7. फंडिंग :

निवेश अवसरों तक पहुँच की सुविधा के लिए सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सुविधाजनक शर्तों (जैसे सम-पारिक्क मुक्त ऋण, उदार शर्तों पर ऋण इत्यादि) पर शुरूआती उधार देने की अपनी वर्तमान योजनाओं को बढ़ाने और विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

7.1. ऐंजेल नेटवर्क की स्थापना :

स्टार्ट-अप के लिए सीड फण्ड उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार उच्च निबल मूल्य वाले व्यक्तियों, उद्योगपतियों, सफल उद्यमियों, विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों तथा उच्च अनुभवी व्यवसायिक कार्यकारियों एवं पेशेवरों को ऐंजेल नेटवर्क (उत्तराखण्ड ऐंजल्स) तथा "सामाजिक प्रभाव निवेशक समूह" स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

7.2. मैचिंग ग्रांट :

राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर्स को, जो भारत सरकार के सीड फण्ड योजना का प्रबन्धन कर रहे हैं, को अतिरिक्त वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के बराबर अथवा अधिकतम ₹ 2 करोड़ जो भी कम हो, देय होगा।

7.3. अन्य सहयोग :

भारत सरकार द्वारा स्टार्ट-अप को प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ जैसे-निरीक्षणों से छूट, करों में छूट तथा स्वप्रमाणन आदि को राज्य में लागू किए जाने के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

8. अकादमिक सहयोग :**8.1. पाठ्यक्रम अद्यतन :**

स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अपने संबंधित पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने के लिए "उद्यमिता विकास" पर अनिवार्य पाठ्यक्रमों को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने की सलाह दी जाएगी, ताकि उद्यमिता के प्रति प्रेरणा, क्षमता और झुकाव वाले छात्रों को प्रेरित किया जा सके।

8.2. पाठ्यक्रम में विस्तृत "ओपन-ऑनलाइन" पाठ्यक्रम का समावेश :

उद्यमशीलता पर केन्द्रित विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विस्तृत "ओपन-ऑनलाइन" पाठ्यक्रम को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन विस्तृत "ओपन-ऑनलाइन" पाठ्यक्रम को छात्रों द्वारा ऐच्छिक रूप में लिया जा सकता है और उनकी इच्छा के आधार पर उन्हें सौंपा जा सकता है।

8.3. ई0डी0सी0 (उद्यमिता विकास सेल) नेटवर्क की स्थापना :

महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को, कॉलेज स्तर पर छात्रों को उद्यमिता लेने के लिए प्रोत्साहित करने तथा ई0डी0सी0 स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। उद्यमिता विकास सेल हब का एक हिस्सा होंगे और आदर्श मॉडल की तरह संबंधित संस्थानों में प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण और व्यावसायीकरण को सुविधाजनक बनाने में सहायता करेंगे। आई0आई0टी0, रुड़की तथा आई0आई0एम0, काशीपुर में दो फोकल एंटरप्रेन्योरेशिय प्रोडक्टिंग बॉडीज (ई0पी0बी0) की शुरुआत की जाएगी।

8.4. प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण :

नवाचार और उद्यमिता शिक्षक युवाओं को आविष्कार के लिए प्रेरित कर सकते हैं। स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र से उद्योग के दिग्गजों, कॉर्पोरेट और अन्य नेताओं द्वारा स्थानीय संकाय को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जायेगा।

8.5. परियोजना कार्य :

अपने स्नातक स्तर के किसी भी वर्ष में स्टार्ट-अप विचारों पर काम करने वाले छात्र उद्यमी को अपनी आरम्भिक परियोजना के रूप में अपनी शुरुआत की परियोजना को अपनी डिग्री पूर्ण करने के लिए परिवर्तित करने की अनुमति होगी।

9. अन्य पहल :

9.1. मेन्टरशिप बूटकैम्प :

सरकार आवश्यक रूप से स्कूलों और कॉलेजों में बूट शिविर स्थापित करके स्कूल और कॉलेज स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। ये बूटकैम्प राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय इन्क्यूबेटर, त्वरक, स्टार्ट-अप इवेंजिलिस्ट और उद्योग संघों के साथ साझेदारी में किए जाएंगे। इससे—

1. भाग लेने वाले छात्रों और उद्यमियों को आवश्यक सलाह मिलेगी।
2. वैश्विक सर्वोत्तम प्रयोगों की सूचना प्राप्त हो सकेगी।

9.2. आइडिया चैलेंज :

उद्यमिता की भावना को विकसित/बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक मण्डल में प्रत्येक छः माह में "आइडिया चैलेंज" आयोजित किया जायेगा। विजेता नवाचारी को, जिनकी संख्या अधिकतम 10 तक हो सकती है, ₹ 50,000.00 (रु0 पचास हजार) का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

9.3. नवोन्मेषों का वार्षिक स्टार्ट-अप फेस्टिवल :

उद्यमिता और नवाचार के लिए नवोन्मेषों का वार्षिक फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा, जिससे युवाओं को समस्या हल करने की मानसिकता और उद्यमिता को लेकर प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे—

1. नवोन्मेषों के प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा।
2. स्थानीय पारिस्थिकी तंत्र के हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा।

10. सक्षमता :

उत्तराखण्ड की स्टार्ट-अप नीति को सुचारु क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार निम्न सुनिश्चित करेगी—

10.1. स्टार्ट-अप पोर्टल और मोबाइल ऐप :

राज्य सरकार एक स्टार्ट-अप पोर्टल और ऐप विकसित करेगी, जिसमें नीति से संबंधित सभी सूचनाएँ, इसके लाभ और उन्हें लेने की प्रक्रिया की सूचनाएँ उपलब्ध होंगी।

10.2. समर्पित हेल्पलाइन :

सभी स्टार्ट-अप से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन अंग्रेजी और हिन्दी में सक्रिय की जाएगी। हेल्पलाइन व्यवसाय के पंजीकरण, धन/ऋण की उपलब्धता की जानकारी, नीति का स्पष्टीकरण इत्यादि जैसे क्षेत्रों में सभी प्रश्नों को सम्बोधित करने में सहायता करेगी।

10.3. प्रोत्साहन :

राज्य सरकार उत्तराखण्ड को अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी के माध्यम से एक स्टार्ट-अप गंतव्य के रूप में बढ़ावा देगी, ऐसे आयोजनों में स्थानीय स्टार्ट-अप और अन्य विभिन्न माध्यमों की भागीदारी को प्रायोजित किया जाएगा।

10.4. समीक्षा तंत्र :

टास्क फोर्स द्वारा इस नीति की समीक्षा एक वर्ष में एक बार अवश्य की जाएगी, ताकि नीति की उपयोगिता का ऑकलन, कार्यान्वयन में आसानी और परिणाम प्राप्त हो सकें। यह रिपोर्ट स्टार्ट-अप परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी।

यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय पत्र संख्या 196/XXVII(8)/2018, दिनांक 22 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

आज्ञा से,
मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

23 फरवरी, 2018 ई०

संख्या 88/XIX-1/18-141/2006-एतद्वारा श्री राहुल शर्मा, जिला पूर्ति अधिकारी, हरिद्वार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उपायुक्त (खाद्य), वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600 [7वें वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स (लेविल-11) ₹ 67,700-2,08,700] के पद पर अस्थाई रूप से पदोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. पदोन्नति के फलस्वरूप श्री राहुल शर्मा को उपायुक्त (खाद्य) के पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उपायुक्त (खाद्य) के पद पर श्री शर्मा की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे। अतः श्री शर्मा द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी, हरिद्वार का कार्य पूर्ववत् सम्पादित किया जायेगा और योगदान आख्या की सूचना शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।

4. प्रश्नगत पदोन्नति उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अन्तिम आवंटन के अधीन होगी। भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शी समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश के अन्य कार्मिक उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं, तो तदपरिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में, इस आदेश को, तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

23 फरवरी, 2018 ई०

संख्या 263/XIX-1/18-141/2006-एतद्वारा सुश्री निधि रावत, जिला पूर्ति अधिकारी, वर्तमान में सहायक आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग में तैनात, को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उपायुक्त (खाद्य), वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600 [7वें वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स (लेविल-11) ₹ 67,700-2,08,700] के पद पर अस्थाई रूप से पदोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. पदोन्नति के फलस्वरूप सुश्री निधि रावत को उपायुक्त (खाद्य) के पद पर 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3. उपायुक्त (खाद्य) के पद पर सुश्री निधि रावत की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे। अतः सुश्री निधि रावत द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड में पूर्ववत् कार्य सम्पादित किया जायेगा और योगदान आख्या की सूचना शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।

4. प्रश्नगत पदोन्नति उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अन्तिम आवंटन के अधीन होगी। भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शी समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश के अन्य कार्मिक उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं, तो तदपरिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में, इस आदेश को, तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

आज्ञा से,
आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग-1

आदेश

24 फरवरी, 2018 ई०

संख्या 205/XX-1-2018-2(20)2009-एतद्वारा डॉ० असीम श्रीवास्तव, आई०पी०एस०, पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि०, देहरादून को दिनांक 01 मार्च, 2018 की पूर्वाह्न से परिसहाय, श्री राज्यपाल (पुलिस), उत्तराखण्ड के पद पर तैनात किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्तानुसार स्थानान्तरित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे यथानिर्दिष्ट तिथि एवं समय पर परिसहाय, श्री राज्यपाल (पुलिस), उत्तराखण्ड के पद का कार्यभार ग्रहण करते हुए, कार्यभार ग्रहण प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

अधिसूचना

23 मार्च, 2018 ई0

संख्या 628/XVII-3/18-03(14)/2017-“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत वैयक्तिक सहायक (कम्प्यूटर दक्ष) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग वैयक्तिक सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2017भाग 1-“सामान्य”

- | | |
|------------------------|--|
| संक्षिप्त नाम और आरम्भ | 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम “उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग वैयक्तिक सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2017” है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| सेवा की प्राप्ति | 2. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग वैयक्तिक सहायक (कम्प्यूटर दक्ष) सेवा है, जिसमें समूह-‘ग’ के पद सम्मिलित हैं। |
| परिभाषाएँ | 3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:-
(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
(ख) “भारत का नागरिक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;
(ग) “संविधान” से भारत का संविधान अभिप्रेत है;
(घ) “आयोग” से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है;
(ङ) “सरकार” से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
(च) “राज्यपाल” से उत्तराखण्ड के श्री राज्यपाल महोदय अभिप्रेत है;
(छ) “सेवा का सदस्य” से इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थाई रूप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
(ज) “सेवा” से उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग वैयक्तिक सहायक संवर्ग सेवा अभिप्रेत है;
(झ) “मौलिक नियुक्ति” से किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;
(ञ) “भर्ती का वर्ष” से किसी कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि अभिप्रेत है; |

भाग 2— "संवर्ग"

- सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उत्तनी होगी, जो समय-समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय।
- (2) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों के द्वारा परिवर्तित न की जाय, उत्तनी होगी जितनी परिशिष्ट-क में दी गई है;
- परन्तु यह कि -
- (क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित रख सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी एवं अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

भाग 3— "भर्ती"

- भर्ती का स्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :-

क्र. पदनाम	भर्ती का स्रोत या पदोन्नति का मापदण्ड
1 वैयक्तिक सहायक (कम्प्यूटर दक्ष)	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से।
2 वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वैयक्तिक सहायक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 08 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
3 वैयक्तिक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के रूप में) न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कुल 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

- आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4— "अर्हतायें"

- राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी—
- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा कीनिया, युगाण्डा और संयुक्त तन्जानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्ववर्ती देशों से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा ;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है, तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी— जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और ना ही नामजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

आयु

8.

वैयक्तिक सहायक (कम्प्यूटर दक्ष) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए।

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य ऐसे श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

शैक्षिक अर्हताएं

9.

वैयक्तिक सहायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु निम्न शैक्षिक अर्हता होना आवश्यक है :—

(क) उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता,

(ख) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसायटी द्वारा संचालित 01 वर्षीय कम्प्यूटर पाठ्यक्रम अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 01 वर्षीय कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है,

- (ग) हिन्दी आशुलेखन परीक्षा के लिए न्यूनतम 80 (अस्सी) शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 8000 KDPH की न्यूनतम गति निर्धारित होगी।
- (घ) अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा के लिए न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 9000 KDPH की न्यूनतम गति निर्धारित होगी।
- (ङ) अनिवार्य/वाछनीय आर्हता— सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।
- अधिमानी अर्हताएं 10. ऐसे अभ्यर्थी को अन्य बातें समान होते हुए, सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने—
(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या
(दो) नेशनल कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
- चरित्र 11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं का समाधान कर लेगा।
टिप्पणी— संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
- वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थिनी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो ;
परन्तु यह कि यदि सरकार को समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।
- शारीरिक स्वस्थता 13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—दो, भाग तीन के अध्याय—तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग 5—"भर्ती की प्रक्रिया"

रिक्तियों की अवधारणा 14.

नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सूचित करते हुए उसकी सूचना सेवायोजन कार्यालय को देगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15.

उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008 के अनुसार आयोग के माध्यम से की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 16.

(क) इस सेवा के पदोन्नति के पदों पर भर्ती हेतु चयन समिति "उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2012" (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार निम्नवत् गठित की जायेगी :-

(एक)	विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी	- अध्यक्ष
(दो)	अपर विभागाध्यक्ष/समंकक्ष अधिकारी	- सदस्य
(तीन)	सहायक निदेशक	- सदस्य
(चार)	उप निबंधक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्	- सदस्य

(ख) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा गुणानुक्रम के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी, और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के सम्मुख रखी जायेगी, जो उचित समझ जायें।

(ग) चयन समिति द्वारा उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा।

(घ) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

(ङ) पदोन्नति पर न जाने वाले अभ्यर्थियों की पदोन्नति पर आगामी दो वर्ष तक विचार नहीं किया जायेगा।

संयुक्त चयन सूची 17.

यदि किसी वर्ष में नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति, दोनों प्रकार से की जाती है, तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग 6—"नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता"

नियुक्ति

18. (1) उपनियम (2) के अध्याधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 15, 16 अथवा 17, यथास्थिति, के अधीन बनायी गई सूचियों में हो, नियुक्ति करेगा।

- (2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हैं, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जाएंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया गया हो और नियम 17 के अनुसार संयुक्त सूचियां तैयार न कर ली गयी हो।
- (3) यदि किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो चयनित व्यक्तियों के नाम नियम 17 में निर्दिष्ट क्रम में क्रमांकित किये जाएंगे।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्त पद पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रहेगा।

- (2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक-पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जब तक अवधि बढ़ायी गई है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे,

परन्तु यह कि अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि 04 वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में 02 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

- (3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा, की बढ़ायी गई अवधि में परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है, तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

- (4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो, या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होंगे।

- (5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किसी पद पर अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

20. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा, यदि -

- (क) उसका कार्य व आचरण संतोषजनक बताया गया हो;
- (ख) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रायित है, तथा
- (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

21. (1) एतदपश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवा (ज्येष्ठता निर्धारण) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उनके नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं।

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा।

परन्तु यह और कि यदि चयन के पश्चात् किसी के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं, तो ज्येष्ठता वह होगी, जो नियम 18 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

- (2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय।

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है। कारणों की वैधता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

- (3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी, जो उनके संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

- (4) जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा एक से अधिक स्रोतों द्वारा की जाती हैं और स्रोतों का पृथक्-पृथक् कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 17 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे।

परन्तु यह कि —

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्ति विहित कोटे से अधिक की जाती है वहां कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे कर दी जायेगी।

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी, जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गई। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) में उनका नाम चक्रीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(तीन) जहां नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियां संगत नियत या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती हैं और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियां की जाती हैं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति इसके कोटे की रिक्ति के विरुद्ध की गयी है।

भाग-7- "वेतन आदि"

- | | | |
|-------------------------|-----|--|
| वेतनमान | 22. | (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। |
| | | (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट - 'क' के अनुसार होंगे। |
| परिवीक्षा के दौरान वेतन | 23. | (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि पहले से स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहां विहित हो, समसमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी। |

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्य निर्देश न दें, ऐसी बढ़ायी गई अवधि वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

- (2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

परन्तु यह कि, यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो तब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ायी गई अवधि वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

- (3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकार सेवा में है, राज्य के कार्यों से संबंधित सामान्यतः सेवारत सरकार सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग-8- "अन्य प्राविधान"

- पक्ष समर्थन** 24. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी संस्तुति पर, चाहे लिखित हो अथवा मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का प्रमाण उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।
- अन्य विषयों का विनियमन** 25. ऐसे विषयों के संबंध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से संबंधित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।
- सेवा शर्तों का शिथिलीकरण** 26. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है, तो वह इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के संबंध में न्यायोचित तथा साम्यता पूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।
परन्तु यह कि जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहां नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।
- व्यावृत्ति** 27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग वैयक्तिक सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2017

परिशिष्ट-क

(नियम 4 और 22 देखिये)

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग वैयक्तिक सहायक संवर्ग के पदनाम, पदों की संख्या और वेतनमान

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	वैयक्तिक अधिकारी	01	स्तर-7 (₹ 44,900-1,42,400)
2.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	01	स्तर-6 (₹ 35,400-1,12,400)
3.	वैयक्तिक सहायक। (कम्प्यूटर दक्ष)	02	स्तर-5 (₹ 29,200-92,300)
	योग-	04	

आज्ञा से,

कै० आलोक शेखर तिवारी,

अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 628.XVII-3/2018-03(14)/2017, Dated March, 23, 2018 for General information.

NOTIFICATION

March 23, 2018

No. 628.XVII-3/2018-03(14)/2017—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Minority Welfare Department Personal Assistant (Computer efficient) Service.

THE UTTARAKHAND MINORITY WELFARE DEPARTMENT PERSONAL ASSISTANT SERVICE RULES, 2017

PART-I—"GENERAL"

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Short Title and commencement | 1. (1) These rules may be called the "Uttarakhand Minority Welfare Department Personal Assistant Service Rules, 2017"
(2) It shall come into force at once. |
| Status of the Service | 2. The Uttarakhand Minority Welfare Department Personal Assistant (Computer efficient) is a Service, comprising Group 'C' posts. |
| Definition | 3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context -
(a) 'Appointing Authority' means the Director, Minority Welfare Department, Uttarakhand;
(b) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;
(c) 'Constitution' means the Constitution of India;
(d) 'Commission' means the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission;
(e) 'Government' means the Government of Uttarakhand;
(f) 'Governor' means the Governor of Uttarakhand;
(g) 'Member of the service' means a person substantively appointed under these rules of or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of the service;
(h) 'Service' means the Uttarakhand Minority Welfare Department Personal Assistant Cadre Service;
(i) 'Substantive appointment' means an appointment, not being an ad-hoc appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rules, and if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions, issued by the Government.
(j) 'Year of recruitment' means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year. |

PART II- "CADRE"

- Cadre of Service** 4. (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- (2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as specified in Appendix 'A' to these rules.
- Provided that:**
- (a) The Governor may hold in abeyance or the Appointing Authority may leave unfilled any vacant post without thereby entitling any person to compensation, or
- (b) The Governor may create such additional permanent or temporary posts from time to time as he may consider proper.

PART III- "RECRUITMENT"

- Source of Recruitment** 5. (1) Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the source given below:

S.L.	Name of post	Source of recruitment or Criteria of Promotion
(1)	Personal Assistant (Computer Efficient)	Cent percent by Direct recruitment through Commisison.
(2)	Senior Personal Assistant	Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit, from amongst Personal Assistants appointed in a substantive capacity who have satisfactorily completed at least 8 years of service in that capacity on the first day of the year of recruitment.
(3)	Personal Officer	Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit, from amongst Senior Personal Assistants appointed in a substantive capacity who have satisfactorily completed at least 5 years (as a Senior Personal Assistant) or completed 15 years of service on subordinate posts in that capacity on the first day of the year of recruitment.

- Reservation** 6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled tribes, other backward classes and other categories shall be made in accordance with the orders of the State Government in force at the time of recruitment.

PART-IV- "QUALIFICATIONS"**Nationality**

7.

A candidate for direct recruitment to a post in the service must be:

- (a) a citizen of India, or
- (b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
- (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government.

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand.

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such candidate in service beyond a period of one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Age

8.

A candidate for direct recruitment, if posts are advertised between 01 January to 30 June, then on 01 January of the year of recruitment, must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 42 years and if posts are advertised between 01 July to 31 December, then on 01 July of the year of recruitment, must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 42 years.

Provided that upper age limit shall, in the case of candidates belonging to scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes and such other categories as may be notified by the Government from time to time be greater by such number of years as may be specified.

Academic qualifications

9.

For direct recruitment on the Post of Personal Assistant Computer efficient candidates must possess the following academic Qualifications:-

- (a) Must have passed the Intermediate examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or Uttarakhand or an examination recognised as equivalent there to by the Government.

(b) Must have passed 01 year diploma course in Computer application organized by DOEACC Society or by any recognized institution.

(c) The Candidate must have acquired the minimum speed of 80 words per minute in Hindi Shorthand and 8000 KDPH in Hindi Typing on Computer.

(d) The Candidate must have acquired the minimum speed of 100 words per minute in English Shorthand and 9000 KDPH in English Typing on Computer.

(e) **Mandatory/Desirable Qualifications-** The candidate shall be eligible for direct recruitment whose name as registered in any employment office in State of Uttarakhand.

Preferential qualifications 10. Other things being equal, preference shall be given to the candidate in the matter of direct recruitment who has:

- (i) Served in the territorial army for a minimum period of two years or
- (ii) Obtained a 'B' or 'C' certificate of National Cadet Corps:

Character 11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The Appointing Authority shall satisfy itself on this point.

NOTE- Persons dismissed by the Union Government by a State Government or by a Local Authority or any Body or Corporation owned or controlled by the Union or State Government shall be deemed ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status 12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate, who has married a man already having a wife living, shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness 13. The Candidate shall not be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be produced a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand Book, Volume II Part III.

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a Candidate recruited by promotion.

PART V- "PROCEDURE FOR RECRUITMENT"**Determination 14.
of vacancies**

The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of the vacancies reserved for the persons belonging to the scheduled casts, scheduled tribes, other backward classes and other categories belonging to State of Uttarakhand under rule 6 and shall intimate the same to the Subordinate service selection commission and as well as employment office.

**Procedure for 15.
direct
recruitment**

Recruitment shall be made through the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission in accordance with 'The Uttarakhand Procedure for Direct Recruitment for Group "c" Posts (outside the purview of the Uttarakhand Public Service Commission) Rules, 2008.

**Procedure for 16.
recruitment by
promotion**

(a) Departmental Promotional Committee for recruitment to the posts of promotion in the service shall in accordance with the Uttarakhand Departmental Promotion Committee Constitution (outside the purview for the post of the Uttarakhand Public Service Commission) Rules, 2012 (as amended from time to time) be constituted as follows:-

- (i) Head of the Department/Appointing Authority - Chairman
- (ii) Additional Head of the Department/Equivalent Officer - Member
- (iii) Assistant Director - Member
- (iv) Deputy Registrar, Uttarakhand Madarsa Education Board- Member

(b) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority, and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them, as may be considered proper.

(c) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(d) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to the Appointing Authority.

(e) In case the Candidate does not join the post following his appointed in promotion to it, shall not be considered for promotion for the next two years.

**Combined 17.
Select List**

If in any year of recruitment appointment has to be made both by the direct recruitment and by promotion a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates in such a manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being the person appointed by promotion.

PART-VI- "APPOINTMENT, PROBATION CONFIRMATION AND SENIORITY"

- Appointment** 18. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the Appointing Authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15, 16 or 17.
- (2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 17.
- (3) If more than one order of appointments is issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order, referred to in rule 17.
- Probation** 19. (1) A person on appointment to a post or Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.
- (2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases, specifying the date up to which the extension is granted:
- Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and, in no circumstance beyond two years.
- (3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.
- (4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.
- (5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or on any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.
- Confirmation** 20. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, as the case may be, if:
- (a) his work and conduct is reported to be satisfactory,

(b) his integrity is certified, and

(c) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

21. (1) Except as hereinafter provided, the seniority of a person shall be determined according to the provisions of "Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002". If two or more persons are appointed together, the seniority of persons in any category of post shall be determined by such order in which their names are arranged in the appointment order:

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person substantively appointed, that date, will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other case, it will mean the date of issue of the order.

Provided also that if more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection the seniority shall be the same as has been mentioned in the joint order of appointment issued under sub-rule (3) of rule 18.

(2) The Seniority inter se of persons appointed directly on the result or any one selection, shall be the same as determined by the Commission or, as the case may be, by Selection Committee:

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of reasons shall be final.

(3) The Seniority inter se of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

(4) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment or from more than one source and the respective quota of the sources is prescribed, the inter se seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order in a combined list, prepared in accordance with Rule 17, in such manner that the prescribed percentage is maintained:

Provided that :-

(i) Where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, from seniority, to subsequent year or years in which there are vacancies in accordance with the quota.

(ii) Where appointments from any sources fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of the year in which their appointments are made, so however, that in the combined list of that year, to be prepared under this Rule, their names shall be placed at the top followed by the names, in the cyclic order, of the other appointees.

(iii) Where, in accordance with the rules or prescribed procedure, the unfilled vacancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant rule or procedure be filled from the other source and appointment in excess of quota are so made, the persons so appointed shall get the seniority of that very year as if they are appointed against the vacancies quota.

PART-VII- "PAY ETC"

Scales of Pay 22. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.
(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules will be as given Appendix 'A'.

Pay during probation 23. (1) Notwithstanding any provisions in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation if he is not already in permanent government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, passed the departmental examination and undergone successfully the training, if any prescribed and the second increment after two years of service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant Fundamental Rules applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

PART-VIII- "OTHER PROVISIONS"

Canvassing 24. No recommendations, either written or oral other than those required under these rules, shall be taken into consideration. Any attempt on the part of candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters 25. In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service 26.

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

Saving 27.

Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes of citizens and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

THE UTTARAKHAND MINORITY WELFARE DEPARTMENT PERSONAL ASSISTANT CADRE SERVICE RULES, 2017

APPENDIX- "A"

Uttarakhand Minority Welfare Department Personal Assistant Cadre Designation, No. of Posts and Scale of Pay

S.No.	Designation	No. of Posts	Scale of Pay
1.	Personal Officer	01	Level-7 (₹ 44,900-1,42,400)
2.	Senior Personal Assistant	01	Level-6 (₹ 35,400-1,12,400)
3.	Personal Assistant (Computer Efficient)	02	Level-5 (₹ 29,200-92,300)
Total		04	

By Order,

Capt. ALOK SHEKHAR TIWARI,

Additional Secretary.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 अप्रैल, 2018 ई0 (चैत्र 24, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

March 17, 2018

No. 52/UHC/XIV-a/53/Admin.A/2015--Ms. Suman, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 27.02.2018 to 09.03.2018 with permission to suffix 10.03.2018 and 11.03.2018 as 2nd Saturday and Sunday holidays.

NOTIFICATION

March 17, 2018

No. 53/UHC/XIV-a/48/Admin.A/2015--Ms. Sahista Bano, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is hereby sanctioned medical leave for 07 days w.e.f. 05.03.2018 to 11.03.2018.

NOTIFICATION

March 17, 2018

No. 54/XIV-a-40/Admin.A/2016--Sri Rajnish Mohan, 4th Additional Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 22 days w.e.f. 16.02.2018 to 09.03.2018 with permission to suffix 10.03.2018 and 11.03.2018 as holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 20, 2018

No. 55/UHC/XIV-a/27/Admin.A/2012--Ms. Chhavi Bansal, Civil Judge (Jr. Div.), Ramnagar, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 07 days w.e.f. 05-03-2018 to 11.03.2018 with permission to prefix 02.03.2018 to 04.03.2018 as Holi holidays and Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 20, 2018

No. 56/UHC/XIV-a/37/Admin.A/2013--Sri Sachin Kumar Pathak, Civil Judge (Jr. Div.), Tehri Garhwal is hereby sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 23.02.2018 to 09.03.2018, with permission to suffix 10.03.2018 and 11.03.2018 as holidays in terms of G.O. No. 819/xxxvii(7)34/2010-11, dated 31.12.2013.

NOTIFICATION

March 22, 2018

No. 57/XIV-a/56/Admin.A/2012--Ms. Seema Dungrakoti, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 27 days w.e.f. 19.02.2018 to 17.03.2018 with permission to prefix 18.02.2018 as Sunday holiday and suffix 18.03.2018 as Sunday holiday, in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011, dated 30.05.2011 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

March 22, 2018

No. 58/UHC/XIV-a/37/Admin.A/2012--Sri Sandip Kumar Tiwari, Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 41 days w.e.f. 05.02.2018 to 17.03.2018 with permission to prefix 04.02.2018 as Sunday holiday and suffix 18.03.2018 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

March 22, 2018

No. 59/UHC/XIV-a/34/Admin.A/2013--Ms. Rashmi Goyal, Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 05.03.2018 to 14.03.2018 with permission to prefix 02.03.2018 to 04.03.2018 as holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 22, 2018

No. 60/UHC/Admin.A/2018—Ms. Kumkum Rani, District & Sessions Judge, Nainital is transferred and posted as District & Sessions Judge, Tehri Garhwal, vice Smt. Meena Tiwari.

NOTIFICATION

March 22, 2018

No. 61/UHC/Admin.A/2018—Sri Alok Kumar Verma, Principal Secretary (Law)-cum-L.R., Government of Uttarakhand, Dehradun is repatriated and posted as District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar, on superannuation of Sri B. S. Dugtal on 31.03.2018.

NOTIFICATION

March 22, 2018

No. 62/UHC/Admin.A/2018—Sri C. P. Bijalwan, Presiding Officer, Labour Court, Dehradun is repatriated and posted as District & Sessions Judge, Nainital, vice Ms. Kumkum Rani.

This order will come into force w.e.f. 02.04.2018.

Note:—Recommendations have been sent to the State Government for the posting of following officers on deputation posts mentioned against their names:—

1. Smt. Meena Tiwari [District & Sessions Judge, Tehri Garhwal]--As Principal Secretary (Law)-cum-L.R. Government of Uttarakhand, Dehradun, vice Sri Alok Kumar Verma. She has also been given additional charge of Principal Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs, Government of Uttarakhand, in addition to her duties.
2. Sri Sikand Kumar Tyagi (Presiding Officer, Food Safety Appellate Tribunal, Haldwani, Distt. Nainital)--As Presiding Officer, Labour Court, Dehradun, vice Sri C. P. Bijalwan.

Above transfers will come into effect after the receipt of respective notifications from the State Government.

By Order of the Court,

Sd/-

NARENDRA DUTT.

Registrar General.

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़

कार्यभार मुक्त प्रमाण-पत्र

05 फरवरी, 2018 ई०

पत्रांक 59/1-02-2017-प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिनांक 05.02.2018 से दिनांक 14.02.2018 तक (दिनांक 04.02.2018, रविवार अवकाश को पूर्वयोजित करते हुए) अर्जित अवकाश का उपभोग किए जाने हेतु मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को आवेदन किया गया है, अर्जित अवकाश स्वीकृत होने की प्रत्याशा में आज दिनांक 03.02.2018 को न्यायालय कार्य के उपरान्त मेरे द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ का कार्यभार छोड़ा गया।

कुलदीप शर्मा,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

पिथौरागढ़।

प्रतिहस्ताक्षरित

ह० (अस्पष्ट),

जनपद न्यायाधीश,

पिथौरागढ़।

कार्यभार ग्रहण प्रमाण—पत्र

20 फरवरी, 2018 ई0

पत्रांक 86/1-02-2017—प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिनांक 05.02.2018 से दिनांक 17.02.2018 तक (दिनांक 04.02.2018, रविवार अवकाश को पूर्वयोजित करते हुए) अर्जित अवकाश का उपभोग किए जाने हेतु मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को आवेदन किया गया है, अर्जित अवकाश स्वीकृत होने की प्रत्याशा में मेरे द्वारा अर्जित अवकाश का उपभोग करने उपरान्त आज दिनांक 19.02.2018 की पूर्वाह्न में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ का कार्यभार ग्रहण किया गया।

कुलदीप शर्मा,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

पिथौरागढ़।

प्रतिहस्ताक्षरित

ह0 (अस्पष्ट),

जनपद न्यायाधीश,

पिथौरागढ़।

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि—अनुभाग)

24 मार्च, 2018 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,

देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 6287/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि—अनुभाग/17-18/देहरादून—उत्तराखण्ड शासन, वित्त, अनुभाग—8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएँ 154/2018/20(120)/XXVII(8)/2017/CT-13, दिनांक 22 मार्च, 2018 एवं 282/2018/20(120)/XXVII(8)/2017/CT-12, दिनांक 24 मार्च, 2018 तथा आयुक्त राज्य कर द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 6237 (i)/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0—विधि/2017-18, दिनांक 23 मार्च, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः अधिसूचना संख्या 118 दिनांक 31 जनवरी, 2018 को, उन बातों के सिवाए विखण्डित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करने, जिन्हें ऐसे विखण्डन से पूर्व किया गया है या जिनके करने का लोप किया गया है; उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 जारी करने तथा माह अप्रैल, 2018 से माह जून, 2018 तक प्ररूप जी0एस0टी0आर0 3ख में विवरणी दाखिल करने के लिए अन्तिम तारीख नियत किया जाना अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर—निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग-8**अधिसूचना****22 मार्च, 2018 ई०**

संख्या 154/2018/20(120)/XXVII(8)/2017/CT-13—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 128 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 118/2018/5(120)/XXVII(8)/2017/CT-6, तारीख 31 जनवरी, 2018 को, उन बातों के सिवाएँ, विखण्डित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिन्हें ऐसे विखण्डन से पूर्व किया गया है या जिनके करने का लोप किया गया है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 07 मार्च, 2018 से प्रभावी होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 154/2018/20(120)/XXVII(8)/2018/CT-13, Dated March 22, 2018 for general information.

NOTIFICATION*March 22, 2018*

No. 154/2018/20(120)/XXVII(8)/2018/CT-13—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (as applicable in Uttarakhand), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to rescind the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 118/2018/5(120)/XXVII(8)/2017/CT-6, dated 31st January, 2018 except things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force with effect from the 07th day of March, 2018.

अधिसूचना

24 मार्च, 2018 ई0

संख्या 282/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT-12-श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 को अग्रेतर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

नियम 117 में संशोधन 2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसमें यहाँ आगे मूल नियम कहा गया है), दिनांक 07 मार्च, 2018 से नियम 117 में, स्तम्भ-1 में दिए गए उपनियम (4) के खण्ड (ख) में, उपखण्ड (iii) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपखण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान उपखण्ड	एतद्वारा प्रतिस्थापित उपखण्ड
(iii) इस स्कीम का लाभ उठाने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अनुसरण में उसके द्वारा रखे माल का ब्यौरा प्ररूप जीएसटी ट्रान-2 में छह कर अवधियों के प्रत्येक के अन्त पर, जिसके दौरान स्कीम परिचालनीय है, कर अवधि के दौरान ऐसे माल की पूर्ति के ब्यौरे इंगित करते हुए, कथन प्रस्तुत करेगा;	(iii) इस स्कीम का लाभ उठाने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (2) के खण्ड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा रखे गये माल के ब्यौरे 31 मार्च, 2018 तक या ऐसी अवधि के भीतर, जैसा परिषद् की सिफारिशों पर आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए, प्ररूप जीएसटी ट्रान 2 में छह कर अवधियों में प्रत्येक के लिए, जिसके दौरान स्कीम परिचालन में है, कर अवधि के दौरान ऐसे माल के पूर्ति के ब्यौरे इंगित करते हुए, कथन प्रस्तुत करेगा;

नियम 138 में संशोधन 3. स्तम्भ-1 में दिए गए "मूल नियम" के वर्तमान नियम 138 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:-

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

138. माल का संचलन और ई-वे बिल के सृजन से पूर्व प्रस्तुत की जाने वाली सूचना-

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल के पारेषण, जिसका मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, का-

(i) किसी पूर्ति के संबंध में संचलन कारित करता है; या

(ii) पूर्ति से भिन्न किसी कारण से संचलन कारित करता है; या

(iii) किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवक पूर्ति के कारण संचलन कारित करता है।

ऐसे संचलन के प्रारम्भ होने से पूर्व, उक्त माल के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में यथाविनिर्दिष्ट सामान्य पोर्टल पर अपेक्षित की जाने वाली ऐसी अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा और उक्त पोर्टल पर एक विशिष्ट सं0 सृजित किया होगा।

परन्तु जहाँ माल एक राज्य में अवस्थित स्वामी से अन्य राज्य में अवस्थित कार्यकर्मकार को भेजा जाता है, तो ई-वे बिल, पारेषण के मूल्य पर ध्यान दिए बिना स्वामी द्वारा सृजित किया जाएगा।

परन्तु यह और कि जहाँ हस्तशिल्प माल एक राज्य से दूसरे में किसी ऐसे व्यक्ति जो धारा 24 के खण्ड (i) और (ii) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्राप्त है, द्वारा परिवहन किया जाता है तो ई-वे बिल, पारेषण के मूल्य पर ध्यान दिए बिना ऐसे व्यक्ति द्वारा सृजित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-1-इस नियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "हस्तशिल्प माल" से वह अर्थ होगा जो इसे उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना सं0 801/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, तारीख 12 अक्टूबर, 2017 में दिया गया है।

स्पष्टीकरण-2-इस नियम के प्रयोजन के लिए, माल पारेषण मूल्य, वह मूल्य होगा, जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसरण में अवधारित किया गया है बीजक, उक्त पारेषण के संबंध में जारी किए गए यथास्थिति, आपूर्ति के बिल या परिदान चालान में घोषित किया गया है और इसके अन्तर्गत दस्तावेजों में भारित केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या उपकर, यदि कोई है, भी सम्मिलित है।

(2) जहाँ माल का परिवहन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पारेषित के रूप में या पारेषिती के रूप में पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के रूप में किया जाता है, चाहे स्वयं के परिवहन में या भाटक पर लिए गए या रेल द्वारा या वायुयान द्वारा या किसी जलयान द्वारा, तो उक्त व्यक्ति या प्राप्तिकर्ता प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख में सूचना प्रस्तुत करने के पश्चात् सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में ई-वे बिल का सृजन कर सकेगा:

परन्तु जहाँ माल का परिवहन रेल द्वारा या वायुयान द्वारा या किसी जलयान द्वारा, किया जाता है, ई-वे बिल आपूर्तिकर्ता या प्राप्तिकर्ता होते हुए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा बनाया जाएगा, जो सामान्य पोर्टल पर निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा:-

(क) प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख में सूचना; और

(ख) यथास्थिति, रेलवे प्राप्ति या वायुयान पारेषण टिप्पण या लदान का बिल की क्रम सं0 और तारीख।

(3) जहाँ उपनियम (2) के अधीन ई-वे बिल सृजित नहीं किया जाता है और माल को सड़क द्वारा परिवहन के लिए परिवहनकर्ता को सौंप दिया जाता है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति परिवहनकर्ता के संबंध में सामान्य पोर्टल पर सूचना प्रस्तुत करेगा और ई-वे बिल को उक्त पोर्टल पर परिवहनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में प्रस्तुत सूचना के आधार पर सृजित किया जाएगा :

परन्तु यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या परिवहनकर्ता अपने विकल्प पर ई-बिल का तब भी सृजन और वहन कर सकेगा, जब पारेषण का मूल्य पचास हजार रुपए से कम है :

परन्तु यह और कि जब संचलन किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा या तो अपने स्वयं के या किसी भाटक पर वाहन या किसी परिवहनकर्ता के माध्यम से कारित किया जाता है तो वह या परिवहनकर्ता अपने स्वयं के विकल्प पर इस नियम में विनिर्दिष्ट रीति में सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में ई-बिल का सृजन कर सकेगा :

परन्तु यह भी कि जहाँ माल का परिवहन राज्य में पारेषक के कारबार के स्थान से परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान से आगे परिवहन के लिए, दस किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है तो पूर्तिकार या यथास्थिति परिवहनकर्ता प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख में वाहन के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं करेंगे।

स्पष्टीकरण-1-इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, जब माल की पूर्ति किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को की जाती है, जो रजिस्ट्रीकृत है तो संचलन को ऐसे प्राप्तिकर्ता द्वारा कारित किया गया कहा जाएगा, यदि माल का संचलन प्रारम्भ होने के समय प्राप्तिकर्ता ज्ञात है।

स्पष्टीकरण-2-ई0 वे बिल, सड़क द्वारा माल के परिवहन के लिए विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 बिल भाग-ख में सूचना नहीं दी जाती है, सिवाय उस दशा के जब परिवहन उपनियम (3) के तीसरे परंतुक और उपनियम (5) के परंतुक के अन्तर्गत आता है।

(4) सामान्य पोर्टल पर ई-वे बिल के सृजन पर सामान्य पोर्टल पर पूर्तिकार, प्राप्तिकर्ता, परिवहनकर्ता को एक विशिष्ट ई-वे बिल संख्या (ईबीएन) उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) जब माल एक वाहन से दूसरे वाहन पर अंतरित किया जाता है तो पारेषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता, जिसमें प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग-क में सूचना प्रदान की है या परिवहनकर्ता, ऐसे अंतरण और माल के परिवहन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में वाहन के ई-वे बिल के ब्यौरे अद्यतन करेगा :

परंतु जहां मालों का परिवहन राज्य में परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान से अंतिमतः पारेषिती के कारबार के स्थान से दस किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है, तो वाहन के ब्यौरों को ई-वे 14-1 में अद्यतन नहीं किया जाएगा।

(5क) पारेषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता जिसने प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में सूचना दी है या परिवहनकर्ता पारेषण के आगे परिवहन के लिए प्ररूप जीएसटीईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख में सूचना अद्यतन करने के लिए जंग रजिस्ट्रीकृत या नामांकित परिवहनकर्ता को ईडब्ल्यूबी-01 बिल सं. समनुदेशित कर सकेगा।

परन्तु एक बार परिवहनकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटीईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख में अद्यतन कर दी जाती है, यथास्थिति, पारेषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता, जिसने प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में सूचना दी है, को किसी अन्य व्यक्ति को ई-वे बिल संख्या समनुदेशित करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(6) उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में ई-वे बिल के सृजन के पश्चात्, जहां बहुल पारेषणों को एक वाहन में परिवहन करना आशयित है तो परिवहनकर्ता ऐसे प्रत्येक पारेषण के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से सृजित ई-वे बिलों की क्रम संख्या को उपदर्शित कर सकेगा और माल के संचलन से पूर्व उक्त सामान्य पोर्टल पर उसके द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-02 में एक समेकित ई-वे बिल का सृजन किया जा सकेगा।

(7) जहां पारेषक या पारेषिती ने उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 का सृजन नहीं किया है और वाहन में ले जाए जाने वाले माल का मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है तो परिवहनकर्ता, यथास्थिति, पूर्ति के बीजक या बिल या परिदान चालान के आधार पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 का सृजन करेगा और माल के संचलन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-02 में समेकित ई-वे बिल का भी सृजन कर सकेगा।

परंतु जहां माल जिनका परिवहन किया जाना है उसकी ई-वाणिज्य परिचालक के माध्यम से आपूर्ति की जाती है वहां ऐसे ई-वाणिज्य परिचालक द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में सूचना दी जा सकेगी।

(8) प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में प्रस्तुत सूचना को सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा जो उसका उपयोग प्ररूप जीएसटीआर-01 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कर सकेगा।

परंतु जहां सूचना गैर-रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार या गैर-रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में प्रस्तुत की गयी है तो उसे इलैक्ट्रानिक रूप से सूचित किया जाएगा, यदि मोबाइल नंबर या ई-मेल उपलब्ध है।

(9) जहां इस नियम के अधीन ई-वे बिल सृजित किया गया है किंतु माल का या तो परिवहन नहीं किया गया है या परिवहन प्रस्तुत ई-वे बिल के ब्यौरों के अनुसार नहीं किया गया है तो ई-वे बिल को सामान्य पोर्टल पर ई-वे बिल के सृजन के चौबीस घंटों के भीतर रद्द किया जा सकेगा।

परंतु किसी ई-वे बिल को रद्द नहीं किया जा सकेगा यदि उसका नियम 138ख के उपबंधों के अनुसार अंतरण में सत्यापन कर दिया गया है।

परंतु यह और कि उपनियम (1) के अधीन उत्पन्न विशिष्ट संख्या प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख के अद्यतन के लिए 72 घंटे तक विधिमान्य होगी।

(10) इस नियम के अधीन सृजित ई-वे बिल या समेकित ई-वे बिल सुसंगत तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित अवधि के लिए स्तंभ (2) में यथावर्णित माल का परिवहन की जाने वाली, देश के भीतर दूरी, के लिए विधिमान्य होगा :

सारणी

क्रम सं.	दूरी	वैधता की अवधि
(1)	(2)	(3)
1.	100 किलोमीटर तक	एक दिन
2.	प्रत्येक 100 किलोमीटर या तत्पश्चात् उसके भाग के लिए	एक अतिरिक्त दिन

परंतु आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, किसी ई-वे बिल की विधिमान्यता की अवधि का उसमें विनिर्दिष्ट माल के कतिपय प्रवर्गों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाए, के लिए विस्तार कर सकेगा :

परंतु यह और कि आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन, जहां माल का परिवहन ई-वे बिल की वैधता अवधि के भीतर नहीं किया जा सकता है, तो परिवहनकर्ता प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख में ब्यौरों को अद्यतन करने के पश्चात् दूसरा ई-वे बिल सृजित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए “सुसंगत तारीख” से वह तारीख अभिप्रेत होगी, जिसको ई-वे बिल का सृजन किया गया है और वैधता की अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जिसको ई-वे बिल का सृजन किया गया है और प्रत्येक दिन की गणना चौबीस घंटों के रूप में की जाएगी ।

(11) उप-नियम (1) के अधीन सृजित ई-वे बिल के ब्यौरों को सामान्य पोर्टल पर निम्नलिखित को उपलब्ध कराया जाएगा-

(क) पूर्तिकार को, यदि वह रजिस्ट्रीकृत है, जहां प्रासिकर्ता या परिवाहक द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में जानकारी दी गई है; या

(ख) प्रासिकर्ता को, यदि वह रजिस्ट्रीकृत है, जहां पूर्तिकार या परिवाहक द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में जानकारी दी गई है,

और पूर्तिकार या प्रासिकर्ता, यथास्थिति, वह अपनी ई-वे बिल के अधीन आने वाले पारेषण की स्वीकृति या अस्वीकृति की संसूचना देगा ।

(12) जहां उपनियम (11) में निर्दिष्ट प्रासिकर्ता सामान्य पोर्टल पर ब्यौरों को उसे उपलब्ध कराने के बहतर ढंग के भीतर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति से संसूचित नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि उसने उक्त ब्यौरों को स्वीकार कर लिया है ।

(13) इस नियम या किसी राज्य के माल और सेवाकर नियमों के नियम 138 के अधीन सृजित ई-वे बिल प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में वैध होगा ।

(14) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ई-वे बिल को सृजित करने की अपेक्षा नहीं होगी—

(क) जहां परिवहन किए जा रहे माल को उपाबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ख) जहां माल का परिवहन गैर-मोटरीकृत वाहन द्वारा किया जा रहा है;

(ग) जहां माल का परिवहन किसी पत्तन, विमानपत्तन, एयर कार्गो परिसर और भू-सीमा-शुल्क केंद्र से किसी ई-लैंड कंटेनर डिपो या किसी कंटेनर फ्रेट स्टेशन को सीमा-शुल्क द्वारा अनापत्ति के लिए किया जा रहा है ; और

(घ) ऐसे माल तथा राज्य के ऐसे क्षेत्र के अन्दर के सम्बन्ध में जो केन्द्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त के परामर्श से राज्य कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया हो;

(ङ) जहां डी-ऑयलड केक से भिन्न परिवहन किया गया माल, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक 518/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तारीख 29 जून, 2017 से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है;

(च) जहां माल, मानव उपभोग के लिए एल्कोहल लिकर, पेट्रोलियम अपरिस्कृत, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (जिसे सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन; और

(छ) जहां परिवहन किए जाने वाले माल को अधिनियम की अनुसूची 3 के अधीन किसी आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाता है।

स्पष्टीकरण—ई-वे बिल के सृजन और रद्द करने की सुविधा को एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

उपाबंध
[(देखें नियम 138(14))]

क्र.सं.	माल का विवरण
(1)	(3)
1.	परिवार और गैर-घरेलू छूट वाले प्रवर्ग (एनडीइसी) ग्राहकों के लिए द्वितीयक पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति
2.	पीडीएस के अधीन बिक्रीत मिट्टी का तेल
3.	डाक विभाग द्वारा परिवहन किए गए डाक सामान
4.	असली या कल्चरी मोती और कीमती या कम मूल्य के रत्न ; कीमती धातु और कीमती धातु की परत वाले धातु
5.	आभूषण, स्वर्णकार और रजतकार सामग्री और अन्य वस्तुएं (अध्याय-71)
6.	करेंसी
7.	निजी और घरेलू प्रभाव के उपयोग
8.	प्रवाल, अकर्मित(0508) और कर्मित प्रवाल(9601).";

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

138. माल का संचलन और ई-वे बिल के सृजन से पूर्व प्रस्तुत की जाने वाली सूचना—

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल के पारेषण, जिसका मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, का—

- (i) किसी पूर्ति के संबंध में संचलन कारित करता है ; या
- (ii) पूर्ति से भिन्न किसी कारण से संचलन कारित करता है ; या
- (iii) किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवक पूर्ति के कारण संचलन कारित करता है,

ऐसे संचलन के प्रारंभ होने से पूर्व, उक्त माल के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में यथाविनिर्दिष्ट सामान्य पोर्टल पर अपेक्षित की जाने वाली ऐसी अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा और उक्त पोर्टल पर एक विशिष्ट संख्या सृजित की जाएगी।

परंतु परिवाहक, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त प्राधिकार पर, ऐसी अन्य जानकारी, जैसा सामान्य पोर्टल पर अपेक्षित हो, के साथ साथ सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-01 के भाग क में जानकारी देगा और उक्त पोर्टल पर एक विशिष्ट संख्या सृजित की जाएगी:

परंतु यह और कि जहां मालों का परिवहन किसी ई- वाणिज्य आपरेटर या कोरियर एजेंसी के माध्यम से किया जाता है या आपूर्ति किया जाता है वहां आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त प्राधिकार पर ऐसे ई-वाणिज्य आपरेटर या कोरियर एजेंसी द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में जानकारी दी जाएगी और उक्त पोर्टल पर एक विशिष्ट संख्या सृजित की जाएगी:

परंतु यह भी कि जहां माल एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित प्रधान से अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कार्यकर्मकार को भेजा जाता है, वहां ई-वे बिल, पारेषण के मूल्य पर ध्यान दिए बिना प्रधान या रजिस्ट्रीकृत हो तो, कर्मकार द्वारा सृजित की जाएगी।

परंतु यह भी कि जहां हस्तशिल्प माल एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से दूसरे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति जो धारा 24 के खंड (i) और (ii) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्राप्त है, द्वारा परिवहन किया जाता है तो ई-वे बिल, पारेषण के मूल्य पर ध्यान दिए बिना ऐसे व्यक्ति द्वारा सृजित किया जाएगा"

स्पष्टीकरण 1 - इस नियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "हस्तशिल्प माल" से वह अर्थ होगा जो इसे, समय-समय पर यथासंशोधित, उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 801/2017/ 9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 में दिया गया है।

स्पष्टीकरण 2 - इस नियम के प्रयोजन के लिए माल का पारेषण मूल्य वह मूल्य होगा जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसरण में अवधारित किया गया है, उक्त पारेषण के संबंध में जारी किए गए यथास्थिति, बीजक, आपूर्ति के बिल या परिदान चालान में घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत केन्द्रीय कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर अथवा दस्तावेजों में प्रभारित किया गया सैस, यदि कोई हो, भी है और इसमें छूट प्राप्त माल का मूल्य अपवर्जित है, जहां बीजक दोनों आपूर्तियों, छूट प्राप्त तथा कराधेय आपूर्ति हेतु जारी किया गया है।

(2) जहां सड़क द्वारा माल का परिवहन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति परेषित के रूप में या परेषिती के रूप में पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के रूप में चाहे स्वयं के परिवहन में या एक भाटक या सार्वजनिक वाहन पर किया जाता है, तो उक्त व्यक्ति प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख में सूचना प्रस्तुत करने के पश्चात् सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में ई-वे बिल का सृजन कर सकेगा:

(2क) जहां मालों का परिवहन रेल द्वारा या वायुयान या जलयान द्वारा किया जाता है वहां ई-वे बिल रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा सृजित किया जायेगा, पूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता या तो मालों के संचलन के प्रारंभ से पहले या बाद में सामान्य पोर्टल पर जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख में जानकारी देगा:

परंतु जहां मालों का परिवहन रेल द्वारा किया जाता है वहां रेलवे तब तक मालों का परिदान नहीं करेगा जब तक कि इन नियमों के अधीन अपेक्षित ई-वे बिल परिदान करते समय प्रस्तुत नहीं किया जाता।

(3) जहां उपनियम (2) के अधीन ई-वे बिल सृजित नहीं किया जाता है और माल को सड़क द्वारा परिवहन के लिए परिवहनकर्ता को सौंप दिया जाता है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति परिवहनकर्ता के संबंध में सामान्य पोर्टल पर सूचना प्रस्तुत करेगा और ई-वे बिल को उक्त पोर्टल पर परिवहनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में प्रस्तुत सूचना के आधार पर सृजित किया जाएगा:

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या परिवहनकर्ता अपने विकल्प पर ई-वे बिल का तब भी सृजन और वहन कर सकेगा जब पारेषण का मूल्य पचास हजार रुपए से कम है:

परंतु यह और कि जब संचलन किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा या तो अपने स्वयं के या किसी भाटक पर वाहन या किसी परिवहनकर्ता के माध्यम से कारित किया जाता है तो वह या परिवहनकर्ता अपने स्वयं के विकल्प पर इस नियम में विनिर्दिष्ट रीति में सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में ई-वे बिल का सृजन कर सकेगा:

परंतु यह भी कि जहां माल का परिवहन राज्य में पारेषक के कारबार के स्थान से, परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान तक आगे परिवहन के लिए, पचास किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है तो पूर्तिकार या प्राप्तिकर्ता या यथास्थिति परिवहनकर्ता प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख में वाहन के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं करेंगे।

स्पष्टीकरण 1.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए जब माल की पूर्ति किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को की जाती है जो रजिस्ट्रीकृत है तो संचलन को ऐसे प्राप्तिकर्ता द्वारा कारित किया गया कहा जाएगा यदि माल का संचलन प्रारंभ होने के समय प्राप्तिकर्ता ज्ञात है।

स्पष्टीकरण 2.- ई वे बिल, सड़क द्वारा माल के परिवहन के लिए विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 बिल भाग-ख में सूचना नहीं दी जाती है, सिवाय उस दशा के जब परिवहन उपनियम (3) के तीसरे परंतुक और उपनियम (5) के परंतुक के अंतर्गत आता है।

(4) सामान्य पोर्टल पर ई-वे बिल के सृजन पर सामान्य पोर्टल पर पूर्तिकार, प्राप्तिकर्ता, परिवहनकर्ता को एक विशिष्ट ई-वे बिल संख्या (ईबीएन) उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) जब माल एक वाहन से दूसरे वाहन पर अंतरित किया जाता है तो पारेषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता जिसने प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में सूचना प्रदान की है या परिवहनकर्ता, ऐसे अंतरण और माल के परिवहन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख में वाहन के ब्यौरे ई-वे बिल में अद्यतन करेगा:

परंतु जहां मालों का परिवहन राज्य में परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान से अंतिमतः पारेषिती के कारबार के स्थान तक पचास किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है, तो वाहन के ब्यौरों को ई-वे बिल में अद्यतन नहीं किया जायेगा।

(5क) पारेषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता जिसने प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में वाहन के ब्यौरे की सूचना दी है या परिवहनकर्ता पारेषण के आगे परिवहन के लिए प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख में सूचना अद्यतन करने के लिए अन्य रजिस्ट्रीकृत या नामांकित परिवहनकर्ता को ईडब्ल्यूबी-01 बिल संख्या समनुदेशित कर सकेगा।

परन्तु परिवहनकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख में अद्यतन करने के पश्चात्, यथास्थिति पारेषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता, जिसने प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में सूचना दी है, को किसी अन्य व्यक्ति को ई-वे बिल संख्या समनुदेशित करने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(6) उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में ई-वे बिल के सृजन के पश्चात्, जहां बहुल पारेषणों को एक वाहन में परिवहन करना आशयित है तो परिवहनकर्ता ऐसे प्रत्येक पारेषण के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित ई-वे

बिलों की क्रम संख्या को उपदर्शित कर सकेगा और माल के संचलन से पूर्व उक्त सामान्य पोर्टल पर उसके द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-02 में एक समेकित ई-वे बिल का सृजन किया जा सकेगा।

(7) जहां परेषक या परेषिती ने ई-वे बिल का सृजन प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में नहीं किया है और वाहन में ले जाए जाने वाले माल के परेषण का कुल योग मूल्य पचास हजार रुपये से अधिक है तो परिवाहक, यथास्थिति, पूर्ति के बीजक या प्रदाय का बिल या परिदान चालान के आधार पर ई-वे बिल का सृजन प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में अंतरराज्य पूर्ति की बाबत, रेल, वायुयान और जलयान के सिवाय, करेगा और माल के संचलन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-02 में समेकित ई-वे बिल का भी सृजन कर सकेगा।

परंतु जहां माल जिनका परिवहन किया जाना है उसकी ई-वाणिज्य परिचालक के माध्यम से आपूर्ति की जाती है वहां ऐसे ई-वाणिज्य परिचालक या कोरियर एजेंसी द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में सूचना दी जा सकेगी।

(8) प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में प्रस्तुत सूचना को सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा जो उसका उपयोग प्ररूप जीएसटी आर-01 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कर सकेगा।

परंतु जहां सूचना गैर-रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ता या गैर-रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में प्रस्तुत की गयी है तो उसे इलैक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा, यदि मोबाइल नंबर या ई-मेल उपलब्ध है।

(9) जहां इस नियम के अधीन ई-वे बिल सृजित किया गया है किंतु माल का या तो परिवहन नहीं किया गया है या परिवहन प्रस्तुत ई-वे बिल के ब्यौरों के अनुसार नहीं किया गया है तो ई-वे बिल को सामान्य पोर्टल पर ई-वे बिल के सृजन के चौबीस घंटों के भीतर रद्द किया जा सकेगा।

परंतु किसी ई-वे बिल को रद्द नहीं किया जा सकेगा यदि उसका नियम 138ख के उपबंधों के अनुसार अंतरण में सत्यापन कर दिया गया है।

परंतु यह और कि उपनियम (1) के अधीन उत्पन्न विशिष्ट संख्या प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख के अद्यतन हेतु पंद्रह दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(10) इस नियम के अधीन सृजित ई-वे बिल या समेकित ई-वे बिल सुसंगत तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित अवधि के लिए स्तंभ (2) में यथावर्णित माल का परिवहन की जाने वाली, देश के भीतर दूरी, के लिए विधिमान्य होगा:

सारणी

क्र.सं.	दूरी	वैधता की अवधि
(1)	(2)	(3)
1	100 किलोमीटर तक	एक दिन, ओवर डायमेंशनल कार्गो से अन्यथा के मामलों में
2	प्रत्येक 100 किलोमीटर या तत्पश्चात् उसके भाग के लिए	एक अतिरिक्त दिन, ओवर डायमेंशनल कार्गो से अन्यथा के मामलों में
3	20 किलोमीटर तक	ओवर डायमेंशनल कार्गो की दशा में एक दिन
4	प्रत्येक 20 किलोमीटर या तत्पश्चात् उसके भाग के लिए	ओवर डायमेंशनल कार्गो की दशा में एक अतिरिक्त दिन

परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, किसी ई-वे बिल की विधिमान्यता की अवधि का उसमें विनिर्दिष्ट माल के कतिपय प्रवर्गों, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए, के लिए विस्तार कर सकेगा:

परंतु यह और कि आपवादिक प्रकृति जिसके अंतर्गत पोतांतरण भी है, की परिस्थितियों के अधीन, जहां माल का परिवहन ई-वे बिल की विधिमान्य अवधि के भीतर नहीं किया जा संकता है, तो परिवाहक यदि अपेक्षित हो तो प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख में ब्यौरों को अद्यतन करने के पश्चात् विधिमान्य अवधि को बढ़ा सकेगा।

स्पष्टीकरण 1—इस नियम के प्रयोजनों के लिए "सुसंगत तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत होगी, जिसको ई-वे बिल का सृजन किया गया है और वैधता की अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जिसको ई-वे बिल का सृजन किया गया है और प्रत्येक दिन की गणना ई-वे बिल के सृजन की तारीख के ठीक पश्चात्तवर्ती दिन के मध्यरात्रि को समाप्त होने वाली अवधि के रूप में की जाएगी।

स्पष्टीकरण 2—इस नियम के प्रयोजन के लिए "ओवर डायमेंशनल कार्गो" पद से ऐसा कोई कार्गो अभिप्रेत है जिसका एकल अविभाजीय यूनिट के रूप में प्रवहन किया जा रहा है और जिसकी डायमेंशन सीमाएं मोटर यान अधिनियम

1988(1988 के 59) के अधीन बनाए गए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 93 में विहित डायमेशन सीमाओं से अधिक हैं।

(11) इस नियम के अधीन सृजित ई-वे बिल के ब्यौरों को सामान्य पोर्टल पर निम्नलिखित को उपलब्ध कराया जाएगा-

(क) पूर्तिकार को, यदि वह रजिस्ट्रीकृत है, जहां प्राप्तिकर्ता या परिवहक द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में जानकारी दी गई है; या

(ख) प्राप्तिकर्ता को, यदि वह रजिस्ट्रीकृत है, जहां पूर्तिकार या परिवहक द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में जानकारी दी गई है,

और पूर्तिकार या प्राप्तिकर्ता, यथास्थिति, अपनी ई-वे बिल के अधीन आने वाले पारेषण की स्वीकृति या अस्वीकृति की संसूचना देगा।

(12) जहां उपनियम (11) में निर्दिष्ट जानकारी सामान्य पोर्टल पर ब्यौरों को उसे उपलब्ध कराने के बहत्तर घण्टे के भीतर या माल के परिदान के समय, इसमें से जो भी पूर्वतर हो अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति से संसूचित नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि उसने उक्त ब्यौरों को स्वीकार कर लिया है।

(13) इस नियम या केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के माल और सेवाकर नियमों के नियम 138 के अधीन सृजित ई-वे बिल राज्य में वैध होगा।

(14) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ई-वे बिल को सृजित करने की अपेक्षा नहीं होगी —

(क) जहां परिवहन किए जा रहे माल को उपाबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ख) जहां माल का परिवहन गैर-मोटरिकृत वाहन द्वारा किया जा रहा है;

(ग) जहां माल का परिवहन किसी पत्तन, विमानपत्तन, एयर कार्गो परिसर और भू-सीमा-शुल्क केंद्र से किसी ईन-लैंड कंटेनर डिपो या किसी कंटेनर फ्रेट स्टेशन को सीमा-शुल्क द्वारा अनापत्ति के लिए किया जा रहा है;

(घ) ऐसे माल तथा राज्य के ऐसे क्षेत्र के अन्दर के सम्बन्ध में तथा ऐसी राशि से अधिक मूल्य के लिए, जो केन्द्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त के परामर्श से राज्य कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया हो;

(ङ) जहां डी-ऑयलड केक से भिन्न परिवहन किया गया माल समय-समय पर यथासंशोधित, उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 518/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में उपाबंध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है;

(च) जहां परिवहित किए जा रहे माल, मानव उपभोग के लिए एल्कोहल लिकर, पेट्रोलियम अपरिस्कृत, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (जिसे सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन है;

(छ) जहां परिवहन किए जाने वाले माल की आपूर्ति को अधिनियम की अनुसूची 3 के अधीन किसी आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाता है;

(ज) जहां मालों का परिवहन-

(i) किसी अंतरदेशीय आधान डिपो या किसी आधान माल भाड़ा स्टेशन से सीमा शुल्क बंध पत्र के अधीन किसी सीमा शुल्क पत्तन, विमानपत्तन, वायु कार्गो काम्पलैक्स और भू सीमा-शुल्क स्टेशन को या किसी एक सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क पत्तन से किसी अन्य सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क पत्तन को किया जा रहा है, या

(ii) सीमा शुल्क पर्यवेक्षण या सीमा शुल्क मुद्रा के अधीन किया जा रहा है,

(झ) जहां ऐसे माल जिसका परिवहन किया जा रहा हो नेपाल या भूटान से आने वाली या को जाने वाले पारगमन कार्गो हैं।

(ञ) जहां परिवहन किए जा रहे माल, समय समय पर यथासंशोधित, उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 519/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 तथा अधिसूचना संख्या 842/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 के अधीन कर से छूट प्राप्त है।

(ट) जहां माल का पारेषण किसी रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन रक्षा संगठन द्वारा, आपूर्तिकर्ता या प्राप्तिकर्ता के रूप में किया जाय।

- (उ) जहाँ मालों का पारेषक, रेल द्वारा मालों के परिवहन के लिए केंद्र सरकार, कोई राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी हैं।
- (ड) जहाँ खाली कार्गो कंटेनर का परिवहन किया जा रहा है, और
- (ढ) जहाँ मालों का परिवहन, किसी पारेषक के कारबार के स्थान से किसी तोल सेतु तक उसका वजन करने के लिए या किसी तोल सेतु से वापस उक्त पारेषक के कारबार के स्थान तक 20 किलोमीटर तक की दूरी के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जा रहा है कि मालों का संचलन नियम 55 के अनुसार जारी परिदान चालान से सहयुक्त है।

स्पष्टीकरण—ई-वे बिल के सृजन, रद्द, अद्यतन और सुपुर्दगी की सुविधा को, यथास्थिति, पूर्तिकार, प्राप्तकर्ता और परिवहक को एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

उपाबंध
[(नियम 138(14) देखें)]

क्र.सं.	माल का विवरण
(1)	(2)
1.	परिवार और गैर-घरेलू छूट वाले प्रवर्ग (एनडीइसी) ग्राहकों के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति
2.	पीडीएस के अधीन बिक्रीत मिट्टी का तेल
3.	डाक विभाग द्वारा परिवहन किए गए डाक सामान
4.	असली या कल्चरी मोती और कीमती या कम मूल्य के रत्न; कीमती धातु और कीमती धातु की परत वाले धातु
5.	आभूषण, स्वर्णकार और रजतकार सामग्री और अन्य वस्तुएं (अध्याय-71)
6.	करेंसी
7.	निजी और घरेलू प्रभाव के उपयोग
8.	प्रवाल, अकर्मित(0508) और कर्मित प्रवाल(9601).”;

नियम 138क में संशोधन 4. स्तम्भ-1 में दिए गए “मूल नियम” के वर्तमान नियम 138क के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्—

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
138क प्रवहन के भारसाधक व्यक्ति द्वारा वहन किए जाने वाले दस्तावेज और युक्तियाँ— (1) प्रवहन का भारसाधक व्यक्ति निम्नलिखित वहन करेगा— (क) यथास्थिति, बीजक या प्रदाय का बिल या परिदान चालान; और (ख) रेडियो आवृत्ति पहचान युक्ति, जो प्रवहन पर ऐसी रीति में, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाए, जड़ी हुई है, की या तो वास्तविक रूप से या प्रतिचित्रित ई-वे बिल या ई-वे बिल संख्या की प्रति।	138क. किसी वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा साथ रखे जाने वाले दस्तावेज और युक्तियाँ— (1) किसी वाहन का प्रभारी व्यक्ति -- (क) यथास्थिति, बीजक या पूर्ति बिल या परिदान चालान अपने साथ रखेगा; (ख) भौतिक रूप में ई-वे बिल की प्रति या ई-वे बिल संख्या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाने वाली रीति में वाहन में संनिहित रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान रीति के माध्यम से पहचान युक्ति से प्रतिचित्रण की गई ई-वे बिल संख्या रखेगा; परंतु इस उपनियम की खंड (ख) में उद्धृत कोई बात रेल, वायुयान और जलयान के द्वारा मालों की संचलन की दशा में लागू नहीं होगी।
(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्ररूप जीएसटी आईएनबी-1 में उसके द्वारा जारी किए गए कर बीजक को उक्त पोर्टल पर अपलोड करके सामान्य पोर्टल से बीजक	(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्ररूप जीएसटी आईएनबी-1 में उसके द्वारा जारी किए गए कर बीजक को उक्त पोर्टल पर अपलोड करके सामान्य पोर्टल से बीजक

निर्देश संख्या अभिप्राप्त कर सकेगा और उसे कर बीजक के बदले में उचित अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए प्रस्तुत कर सकेगा तथा ऐसी संख्या अपलोड करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।	निर्देश संख्या अभिप्राप्त कर सकेगा और उसे कर बीजक के बदले में उचित अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए प्रस्तुत कर सकेगा तथा ऐसी संख्या अपलोड करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
(3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (2) के अधीन बीजक अपलोड करता है, वहां प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग 'क' में सूचना प्ररूप जीएसटी आईएनबी-1 में दी गई सूचना के आधार पर सामान्य पोर्टल द्वारा संकलित की जाएगी।	(3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (2) के अधीन बीजक अपलोड करता है, वहां प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग 'क' में सूचना प्ररूप जीएसटी आईएनबी-1 में दी गई सूचना के आधार पर सामान्य पोर्टल द्वारा संकलित की जाएगी।
(4) आयुक्त, अधिसूचना द्वारा परिवाहकों के वर्ग से विशिष्ट रेडियो आवृत्ति पहचान युक्ति की अपेक्षा कर सकेगा और प्रवहण पर युक्त उक्त जड़वा सकेगा तथा माल के संचलन से पूर्व परिवहन पर रेडियो आवृत्ति पहचान युक्ति ई-वे बिल का प्रतिचित्रण कर सकेगा।	(4) आयुक्त, अधिसूचना द्वारा परिवाहकों के वर्ग से विशिष्ट रेडियो आवृत्ति पहचान युक्ति की अपेक्षा कर सकेगा और प्रवहण पर उक्त युक्त जड़वा सकेगा तथा माल के संचलन से पूर्व परिवहन पर रेडियो आवृत्ति पहचान युक्ति ई-वे बिल का प्रतिचित्रण कर सकेगा।
(5) उपनियम (1) के खंड (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां परिस्थितियों में ऐसी अपेक्षा की जाती है, वहां आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, प्रवहण भारसाधक से ई-वे बिल के बजाय, निम्नलिखित दस्तावेजों को वहन करने की अपेक्षा कर सकेगा - (क) कर बीजक या प्रदाय का बिल या प्रवेश पत्र; या (ख) जहां माल प्रदाय के माध्यम से भिन्न कारणों के लिए परिवहन किया जाता है, वहां परिदान चालान।	(5) उपनियम (1) के खंड (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां परिस्थितियों में ऐसी अपेक्षा की जाती है, वहां आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, प्रवहण भारसाधक से ई-वे बिल के बजाय, निम्नलिखित दस्तावेजों को वहन करने की अपेक्षा कर सकेगा - (क) कर बीजक या पूर्ति का बिल या बिल ऑफ एंट्री; या (ख) जहां माल पूर्ति के माध्यम से भिन्न कारणों के लिए परिवहन किया जाता है, वहां परिदान चालान।

नियम 138ख में
संशोधन

5. स्तम्भ-1 में दिए गए "मूल नियम" के वर्तमान नियम 138ख के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्-

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
138ख दस्तावेजों और प्रवहणों का सत्यापन - (1) आयुक्त या इस निमित्त या उसके द्वारा सशक्त अधिकारी सभी अन्तर्राज्यीय और राज्य के भीतर माल के संचलन के लिए वास्तविक रूप में ई-वे बिल या ई-वे बिल संख्या का सत्यापन करने के लिए किसी प्रवहण को बीच में रोकने के लिए समुचित अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा। (2) आयुक्त, उन स्थानों पर, जहां माल के संचलन का सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, रेडियो आवृत्ति पहचान प्रवाचक संस्थापित कराएगा और ज्ञानों के संचलन का सत्यापन ऐसे युक्ति प्रवाचकों के माध्यम से वहां किया जाएगा, जहां ई-वे बिल उक्त युक्ति के साथ प्रतिचित्रित किया गया है। (3) प्रवहणों का वास्तविक सत्यापन आयुक्त द्वारा यथा प्राधिकृत उचित अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा।	138ख. दस्तावेजों और वाहनों का सत्यापन - (1) आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी, समुचित अधिकारी को मालों के सभी अंतरराज्यीय और अंतराज्यीय संचलन के लिए भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ई-वे बिल का सत्यापन करने के लिए किसी वाहन को रोकने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा। (2) आयुक्त, उन स्थानों पर, जहां माल के संचलन का सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, रेडियो आवृत्ति पहचान प्रवाचक संस्थापित कराएगा और यानों के संचलन का सत्यापन ऐसे युक्ति प्रवाचकों के माध्यम से वहां किया जाएगा, जहां ई-वे बिल उक्त युक्ति के साथ प्रतिचित्रित किया गया है। (3) प्रवहणों का वास्तविक सत्यापन आयुक्त द्वारा यथा प्राधिकृत उचित अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

परन्तु कर अपवंचन पर विनिर्दिष्ट सूचना के प्राप्त हो जाने पर, विनिर्दिष्ट प्रवहण का वास्तविक सत्यापन आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का आवश्यक अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् किसी अन्य अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।

परन्तु कर अपवंचन पर विनिर्दिष्ट सूचना के प्राप्त हो जाने पर, विनिर्दिष्ट प्रवहण का वास्तविक सत्यापन आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का आवश्यक अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् किसी अन्य अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।

नियम 138ग में
संशोधन

6. स्तम्भ-1 में दिए गए "मूल नियम" के वर्तमान नियम 138ग के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान उपखण्ड	एतद्वारा प्रतिस्थापित उपखण्ड
<p>138ग माल का निरीक्षण और सत्यापन-</p> <p>(1) अभिवहण में माल के प्रत्येक निरीक्षण की सारांश रिपोर्ट निरीक्षण के चौबीस घण्टे के भीतर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03 के भाग 'क' में उचित अधिकारी द्वारा ऑनलाइन अभिलिखित की जाएगी और प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03 के भाग 'ख' में अन्तिम रिपोर्ट ऐसे निरीक्षण के तीन दिन के भीतर अभिलिखित की जाएगी।</p> <p>(2) जहाँ किसी प्रवहण पर परिवहन किए जा रहे माल का वास्तविक सत्यापन राज्य के भीतर या किसी अन्य राज्य में एक स्थान पर अभिवहण के दौरान किया गया है, वहाँ उक्त प्रवहण का और वास्तविक सत्यापन उस राज्य में तब तक दोबारा नहीं किया जाएगा, जब तक कर अपवंचन से सम्बन्धित विनिर्दिष्ट जानकारी तत्पश्चात् उपलब्ध नहीं करा दी जाती है।</p>	<p>138ग मालों का निरीक्षण और सत्यापन-</p> <p>(1) पारगमन में मालों के प्रत्येक निरीक्षण की एक संक्षिप्त रिपोर्ट समुचित अधिकारी द्वारा निरीक्षण के चौबीस घण्टे के भीतर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03 के भाग क में और ऐसे निरीक्षण के तीन दिन के भीतर उसकी अन्तिम रिपोर्ट प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03 के भाग ख में अभिलिखित की जाएगी।</p> <p>(2) जहाँ किसी वाहन में परिवहन किए जा रहे मालों का राज्य के भीतर या किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी एक स्थान पर पारगमन के दौरान भौतिक सत्यापन किया जाता है, वहाँ उक्त वाहन का राज्य में तब तक आगे और भौतिक सत्यापन नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके पश्चात् कर अपवंचन से संबंधित कोई विनिर्दिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं करा दी जाती है।</p>

नियम 138घ में
संशोधन

7. स्तम्भ-1 में दिए गए "मूल नियम" के वर्तमान नियम 138घ के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान उपखण्ड	एतद्वारा प्रतिस्थापित उपखण्ड
<p>138घ यान को निरुद्ध किए जाने के बारे में सूचना को अपलोड करने की सुविधा-</p> <p>जहाँ कोई यान तीस मिनट से अधिक अवधि के लिए बीच में ही रोक लिया गया है या निरुद्ध कर दिया गया है, वहाँ परिवाहक सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-04 में उक्त सूचना अपलोड कर सकेगा।</p>	<p>138घ यान को निरुद्ध किए जाने से संबंधित जानकारी अपलोड करने संबंधी प्रसुविधा-</p> <p>जहाँ किसी यान को रोका गया है और तीस मिनट से अधिक की अवधि के लिए निरुद्ध किया गया है, वहाँ परिवाहक उक्त जानकारी को सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-04 पर अपलोड कर सकेगा।</p>

प्ररूपों में संशोधन

8. "मूल नियम" के वर्तमान प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01, प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-02, प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03, प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-04 तथा प्ररूप जीएसटी आईएनवी-1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रख दिया जायेगा; अर्थात्:-

"प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01

(नियम 138 देखें)

ई-वे बिल

ई-वे बिल सं0

ई-वे बिल की तारीख

सृजनकर्ता

तारीख, जिसमें विधिमान्य है :

तारीख, जिस तक विधिमान्य है :

भाग-क		
क. 1	आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	
क. 2	प्रेषण का स्थान	
क. 3	प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	
क. 4	परिदान का स्थान	
क. 5	दस्तावेज संख्यांक	
क. 6	दस्तावेज की तारीख	
क. 7	माल का मूल्य	
क. 8	एचएसएन कोड	
क. 9	परिवहन के कारण	
भाग-ख		
ख. 1	सड़क के लिए यान संख्यांक	
ख. 2	परिवहन दस्तावेज संख्यांक/रक्षा यान संख्यांक/ अस्थाई यान रजिस्ट्रीकरण संख्यांक/नेपाल या भूटान यान रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	

टिप्पण :

1. क. 8 में एचएसएन कोड, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पाँच करोड़ रुपये तक वार्षिक आवर्त रखने वाले करदाताओं लिए न्यूनतम दो अंकीय स्तर और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पाँच करोड़ रुपये से ऊपर का वार्षिक आवर्त रखने वाले करदाताओं के लिए चार अंकीय स्तर पर उपदर्शित किया जाएगा।
2. दस्तावेज संख्या कर बीजक, प्रदाय-पत्र, परिदान चालान या प्रवेश-पत्र का हो सकेगा।
3. परिवहन दस्तावेज संख्या, माल रसीद संख्या या रेल रसीद संख्या या वायु मार्ग बिल संख्या या पोत परिवहन पत्र संख्या को उपदर्शित करता है।
4. परिदान का स्थान, परिदान के स्थान का पिन कोड उपदर्शित करेगा।
5. प्रेषण का स्थान, प्रेषण के स्थान में पिन कोड दर्शित करेगा।
6. जहाँ प्रदायकर्ता या प्राप्तिकर्ता रजिस्ट्रीकृत नहीं है, तब, यथास्थिति, स्तम्भ क.1 या स्तम्भ क.3 में "यूआरपी" शब्द भरे जाएंगे।
7. परिवहन के लिए कारण निम्नलिखित में से एक चुना जायेगा:-

कोड	विवरण
1.	प्रदाय
2.	निर्यात या आयात
3.	छुट-पुट कार्य
4.	एसकेडी या सीकेडी
5.	प्राप्तिकर्ता ज्ञात नहीं है
6.	लाइन सेल्स
7.	विक्रय की विवरणी
8.	प्रदर्शनी या मेले
9.	स्वयं के उपयोग के लिए
10.	अन्य

प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-02

(नियम 138 देखें)

समेकित ई-वे बिल

समेकित ई-वे बिल संख्यांक :

समेकित ई-वे बिल की तारीख :

सृजनकर्ता :

यान संख्या :

ई-वे बिलों की संख्या		
ई-वे बिल सं.		

प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03

(नियम 138ग देखें)

सत्यापन रिपोर्ट

भाग क	
अधिकारी का नाम	
निरीक्षण की तारीख	
निरीक्षण का समय	
यान संख्या	
ई-वे बिल संख्या	
कर बीजक या पूर्ति बिल या परिदान चालान या बिल ऑफ एंटी की तारीख	
कर बीजक या पूर्ति बिल या परिदान चालान या बिल ऑफ एंटी की संख्या	
यान के प्रभारी व्यक्ति का नाम	
माल का वर्णन	
घोषित माल की मात्रा	
घोषित माल का मूल्य	
अंतर का संक्षिप्त वर्णन	

क्या माल निरुद्ध किया गया था ?	
यदि नहीं, तो यान निर्मुक्त की तारीख और समय	
भाग ख	
माल की वास्तविक मात्रा	
माल का वास्तविक मूल्य	
संदेय कर	
समेकित कर	
केंद्रीय कर	
राज्य कर	
उपकर	
संदेय शास्ति	
समेकित कर	
केंद्रीय कर	
राज्य कर	
उपकर	
सूचना के ब्यौरे	
तारीख	
संख्या	
निष्कर्ष के सारांश	

प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-04

(नियम 138घ देखें)

निरुद्ध की रिपोर्ट

ई-वे बिल संख्या	
निरुद्ध की अनुमानित स्थिति	
निरुद्ध की अवधि	
प्रभारी अधिकारी का नाम	(यदि ज्ञात हो)
तारीख	
समय	

प्ररूप जीएसटी आईएनवी-1

(नियम 138क देखें)

बीजक संदर्भ संख्या का सृजन

आईआरएन :			तारीख:	
आपूर्तिकर्ता का नाम				
जीएसटीआईएन				
विधिक नाम				
व्यापार नाम, यदि कोई है				
पता				
बीजक की क्रम संख्या				
बीजक की तारीख				
	प्राप्तिकर्ता के ब्यौरे (जिसके नाम बिल बनाया गया)	परेषिति के ब्यौरे (जिसको लदान किया गया)		
जीएसटीआईएन या यूआईएन, यदि उपलब्ध है				
नाम				
पता				
राज्य (नाम और कोड)				
प्रदाय का प्रकार -				
	बी से बी प्रदाय			
	बी से सी प्रदाय			

	प्रतिलोम प्रभार आकर्षित करता है		
	टीसीएस आकर्षित करता है	प्रचालक का जीएसटीआईएन	
	टीडीएस आकर्षित करता है	टीडीएस प्राधिकारी का जीएसटीआईएन	
	निर्यात		
	विशेष आर्थिक जोन को की गई पूर्ति		
	माना गया निर्यात		

क्र.स.	माल का वर्णन	एच.एस.एन.	मात्रा	इकाई	कीमत (प्रति इकाई)	कुल मूल्य	कटौती, यदि कोई है	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर		राज्य कर		समेकित कर		उपकर	
									दर	रकम	दर	रकम	दर	रकम	दर	रकम
	माल भाड़ा															
	बीमा															
	पैकिंग और अग्रेषित प्रभार आदि															
	कुल															
	कुल बीजक मूल्य (अंकों में)															
	कुल बीजक मूल्य (शब्दों में)															

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम

पदनाम या प्रास्थिति:

- जीएसटी आरएफडी-01 में 9. दिनांक 07 मार्च, 2018 से, स्तम्भ-1 में दिए गए "मूल नियम" के वर्तमान जीएसटी आरएफडी-01 में, घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक] के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी निम्नलिखित घोषणा रख दी जायेगी; अर्थात्-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान घोषणा	एतद्वारा प्रतिस्थापित घोषणा
घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक]	घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक]
मैं घोषणा करता हूँ कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के अध्वधीन नहीं है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने माल या सेवाओं या दोनों पर किसी वापसी का लाभ नहीं लिया है और मैंने उन प्रदायों, जिनके सम्बन्ध में प्रतिदाय का दावा किया जाता है, पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।	मैं यह घोषणा करता हूँ कि निर्यात किया गया माल निर्यात शुल्क के अध्वधीन नहीं है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने इस माल या सेवा या दोनों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर/केन्द्रीय कर की प्रतिदायगी का उपभोग नहीं किया है और मैंने इस पूर्ति पर भुगतान किए गए एकीकृत कर के ऐसे प्रतिदाय का दावा नहीं किया है, जिसके संबंध में प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है।
हस्ताक्षर नाम - पदनाम / प्रास्थिति	हस्ताक्षर नाम पदनाम या प्रास्थिति

- जीएसटी आरएफडी-01क में संशोधन 10. दिनांक 07 मार्च, 2018 से, स्तम्भ-1 में दिए गए "मूल नियम" के वर्तमान जीएसटी आरएफडी-01क में, घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक] के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया निम्नलिखित परंतुक रख दिया जायेगा; अर्थात्-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान उपखण्ड	एतद्वारा प्रतिस्थापित उपखण्ड
घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक]	[धारा 54(3) का दूसरा परंतुक]
मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि निर्यात किया गया माल निर्यात शुल्क के अध्वधीन नहीं है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस माल या सेवा या दोनों पर कोई भी प्रतिदायगी का उपभोग नहीं किया है और मैंने उस प्रदाय पर भुगतान किए गए एकीकृत कर के ऐसे प्रतिदाय का कोई दावा नहीं किया है जिसके संबंध में प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है।	"मैं यह घोषणा करता हूँ कि निर्यात किया गया माल निर्यात शुल्क के अध्वधीन नहीं है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने इस माल या सेवा या दोनों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर/केन्द्रीय कर की प्रतिदायगी का उपभोग नहीं किया है और मैंने इस प्रदाय पर भुगतान किए गए एकीकृत कर के ऐसे प्रतिदाय का दावा नहीं किया है, जिसके संबंध में प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है।
हस्ताक्षर नाम - पदनाम/प्रास्थिति	हस्ताक्षर नाम पदनाम या प्रास्थिति

आज्ञा से,
राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 282/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT-12, Dated March 24, 2018 for general information.

NOTIFICATION

March 24, 2018

No. 282/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT-12—In Exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:--

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2018

Short title and Commencement 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2018.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Amendment in Rule 117 2. In rule 117 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter referred to as the ~~Principal Rules~~), with effect from the 07th day of March, 2018, in sub-rule (4), in clause (b), for sub-clause (iii) set out in column-1, the following sub-clause set out in column-2, shall be substituted, namely:-

Column-1	Column-2
Existing sub-clause	Hereby substituted sub-clause
(iii) the registered person availing of this scheme and having furnished the details of stock held by him in accordance with the provisions of clause (b) of sub-rule (2), submits a statement in FORM GST TRAN 2 at the end of each of the six tax periods during which the scheme is in operation indicating therein the details of supplies of such goods effected during the tax period.	(iii) The registered person availing of this scheme and having furnished the details of stock held by him in accordance with the provisions of clause (b) of sub-rule (2), submits a statement in FORM GST TRAN 2 by 31 st March 2018, or within such period as extended by the Commissioner, on the recommendations of the Council, for each of the six tax periods during which the scheme is in operation indicating therein, the details of supplies of such goods effected during the tax period;";

Amendment in 3. For rule 138 of the "Principal Rules", set out in column-1, the following rule set out in column-2, shall be substituted, namely:-

Column-1
Existing rule
<p>138. Information to be furnished prior to commencement of movement of goods and generation of e-way bill-</p> <p>(1) Every registered person who causes movement of goods of consignment value exceeding fifty thousand rupees—</p> <p style="padding-left: 40px;">(i) in relation to a supply; or</p> <p style="padding-left: 40px;">(ii) for reasons other than supply; or</p> <p style="padding-left: 40px;">(iii) due to inward supply from an unregistered person,</p> <p>shall, before commencement of such movement, furnish information relating to the said goods as specified in Part A of FORM GST EWB-01, electronically, on the common portal along with such other information as may be required at the common portal and a unique number will be generated on the said portal:</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that where goods are sent by a principal located in one State to a job worker located in any other State, the e-way bill shall be generated by the principal irrespective of the value of the consignment:</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided further that where handicraft goods are transported from one State to another by a person who has been exempted from the requirement of obtaining registration under clauses (i) and (ii) of section 24, the e-way bill shall be generated by the said person irrespective of the value of the consignment.</p> <p>Explanation 1. – For the purposes of this rule, the expression "handicraft goods" has the meaning as assigned to it in the Government of Uttarakhand Finance section-8, notification No 801/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 12th October, 2017 as amended from time to time.</p> <p>Explanation 2. - For the purposes of this rule, the consignment value of goods shall be the value, determined in accordance with the provisions of section 15, declared in an invoice, a bill of supply or a delivery challan, as the case may be, issued in respect of the said consignment and also includes the central tax, State tax, integrated tax and cess charged, if any, in the document.</p> <p>(2) Where the goods are transported by the registered person as a consignor or the recipient of supply as the consignee, whether in his own conveyance or a hired one or by railways or by air or by vessel, the said person or the recipient may generate the e-way bill in FORM GST EWB-01 electronically on the common portal after furnishing information in Part B of FORM GST EWB-01:</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that where the goods are transported by railways or by air or vessel, the e-way bill shall be generated by the registered person, being the supplier or the recipient, who shall furnish, on the common portal, the-</p> <p style="padding-left: 40px;">(a) information in Part B of FORM GST EWB-01; and</p> <p style="padding-left: 40px;">(b) the serial number and date of the Railway Receipt or the Air Consignment Note or Bill of Lading, as the case may be.</p>

(3) Where the e-way bill is not generated under sub-rule (2) and the goods are handed over to a transporter for transportation by road, the registered person shall furnish the information relating to the transporter on the common portal and the e-way bill shall be generated by the transporter on the said portal on the basis of the information furnished by the registered person in **Part A of FORM GST EWB-01**:

Provided that the registered person or, the transporter, as the case may be may, at his option, generate and carry the e-way bill even if the value of the consignment is less than fifty thousand rupees:

Provided further that where the movement is caused by an unregistered person either in his own conveyance or a hired one or through a transporter, he or the transporter may, at their option, generate the e-way bill in **FORM GST EWB-01** on the common portal in the manner specified in this rule:

Provided also that where the goods are transported for a distance of less than ten kilometers within the State from the place of business of the consignor to the place of business of the transporter for further transportation, the supplier or the recipient, or as the case maybe, the transporter may not furnish the details of conveyance in **Part B of FORM GST EWB-01**.

Explanation 1.— For the purposes of this sub-rule, where the goods are supplied by an unregistered supplier to a recipient who is registered, the movement shall be said to be caused by such recipient if the recipient is known at the time of commencement of the movement of goods.

Explanation 2.— The e-way bill shall not be valid for movement of goods by road unless the information in **Part-B of FORM GST EWB-01** has been furnished except in the case of movements covered under the third proviso to sub-rule (3) and the proviso to sub-rule (5).

(4) Upon generation of the e-way bill on the common portal, a unique e-way bill number (EBN) shall be made available to the supplier, the recipient and the transporter on the common portal.

(5) Where the goods are transferred from one conveyance to another, the consigner or the recipient, who has provided information in **Part- A of the FORM GST EWB-01**, or the transporter shall, before such transfer and further movement of goods, update the details of conveyance in the e-way bill on the common portal in **FORM GST EWB-01**:

Provided that where the goods are transported for a distance of less than ten kilometers within the State from the place of business of the transporter finally to the place of business of the consignee, the details of conveyance may not be updated in the e-way bill.

(5A) The consignor or the recipient, who has furnished the information in **Part-A of FORM GST EWB-01**, or the transporter, may assign the e-way bill number to another registered or enrolled transporter for updating the information in **Part-B of FORM GST EWB-01** for further movement of consignment:

Provided that once the details of the conveyance have been updated by the transporter in **Part B of FORM GST EWB-01**, the consignor or recipient, as the case

maybe, who has furnished the information in **Part-A** of **FORM GST EWB-01** shall not be allowed to assign the e-way bill number to another transporter.

(6) After e-way bill has been generated in accordance with the provisions of sub-rule (1), where multiple consignments are intended to be transported in one conveyance, the transporter may indicate the serial number of e-way bills generated in respect of each such consignment electronically on the common portal and a consolidated e-way bill in **FORM GST EWB-02** maybe generated by him on the said common portal prior to the movement of goods.

(7) Where the consignor or the consignee has not generated **FORM GST EWB-01** in accordance with the provisions of sub-rule (1) and the value of goods carried in the conveyance is more than fifty thousand rupees, the transporter shall generate **FORM GST EWB-01** on the basis of invoice or bill of supply or delivery challan, as the case may be, and may also generate a consolidated e-way bill in **FORM GST EWB-02** on the common portal prior to the movement of goods:

Provided that where the goods to be transported are supplied through an e-commerce operator, the information in **Part A** of **FORM GST EWB-01** may be furnished by such e-commerce operator.

(8) The information furnished in **Part A** of **FORM GST EWB-01** shall be made available to the registered supplier on the common portal who may utilize the same for furnishing details in **FORM GSTR-1**:

Provided that when the information has been furnished by an unregistered supplier or an unregistered recipient in **FORM GST EWB-01**, he shall be informed electronically, if the mobile number or the e-mail is available.

(9) Where an e-way bill has been generated under this rule, but goods are either not transported or are not transported as per the details furnished in the e-way bill, the e-way bill may be cancelled electronically on the common portal, within 24 hours of generation of the e-way bill:

Provided that an e-way bill cannot be cancelled if it has been verified in transit in accordance with the provisions of rule 138B:

Provided further the unique number generated under sub-rule (1) shall be valid for 72 hours for updation of **Part B** of **FORM GST EWB-01**.

(10) An e-way bill or a consolidated e-way bill generated under this rule shall be valid for the period as mentioned in column (3) of the Table below from the relevant date, for the distance, within the country, the goods have to be transported, as mentioned in column (2) of the said Table:-

Table

Sl. no.	Distance	Validity period
(1)	(2)	(3)
1.	Upto 100 km.	One day

2.	For every 100 km. or part thereof thereafter	One additional day
----	--	--------------------

Provided that the Commissioner may, by notification, extend the validity period of e-way bill for certain categories of goods as may be specified therein:

Provided further that where, under circumstances of an exceptional nature, the goods cannot be transported within the validity period of the e-way bill, the transporter may generate another e-way bill after updating the details in Part B of FORM GST EWB-01. **Explanation.**—For the purposes of this rule, the “relevant date” shall mean the date on which the e-way bill has been generated and the period of validity shall be counted from the time at which the e-way bill has been generated and each day shall be counted as twenty-four hours.

(11) The details of e-way bill generated under sub-rule (1) shall be made available to the—
(a) supplier, if registered, where the information in Part A of FORM GST EWB-01 has been furnished by the recipient or the transporter; or
(b) recipient, if registered, where the information in Part A of FORM GST EWB-01 has been furnished by the supplier or the transporter,
on the common portal, and the supplier or the recipient, as the case maybe, shall communicate his acceptance or rejection of the consignment covered by the e-way bill.

(12) Where the person to whom the information specified in sub-rule (11) has been made available does not communicate his acceptance or rejection within seventy two hours of the details being made available to him on the common portal, it shall be deemed that he has accepted the said details.

(13) The e-way bill generated under this rule or under rule 138 of the Goods and Services Tax Rules of any State shall be valid in every State and Union territory.

(14) Notwithstanding anything contained in this rule, no e-way bill is required to be generated—

- (a) where the goods being transported are specified in Annexure;
- (b) where the goods are being transported by a non-motorised conveyance;
- (c) where the goods are being transported from the port, airport, air cargo complex and land customs station to an inland container depot or a container freight station for clearance by Customs;
- (d) in respect of movement of such goods and within such areas in the State as the Commissioner of State tax, in consultation with the Principal Chief Commissioner/Chief Commissioner of Central tax may notify;
- (e) where the goods, other than de-oiled cake, being transported are specified in the Schedule appended to notification No.518/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29th June, 2017 as amended from time to time;
- (f) where the goods being transported are alcoholic liquor for human consumption, petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas or aviation turbine fuel; and

(g) where the goods being transported are treated as no supply under Schedule III of the Act.

Explanation. - The facility of generation and cancellation of e-way bill may also be made available through SMS.

ANNEXURE

[(See rule 138 (14)]

S. No.	Description of Goods
(1)	(2)
1.	Liquefied petroleum gas for supply to household and non domestic exempted category (NDEC) customers
2.	Kerosene oil sold under PDS
3.	Postal baggage transported by Department of Posts
4.	Natural or cultured pearls and precious or semi-precious stones; precious metals and metals clad with precious metal (Chapter 71)
5.	Jewellery, goldsmiths' and silversmiths' wares and other articles (Chapter 71)
6.	Currency
7.	Used personal and household effects
8.	Coral, unworked (0508) and worked coral (9601)";

Column-2

Hereby substituted rule

138. Information to be furnished prior to commencement of movement of goods and generation of e-way bill.-(1) Every registered person who causes movement of goods of consignment value exceeding fifty thousand rupees—

- (i) in relation to a supply; or
- (ii) for reasons other than supply; or
- (iii) due to inward supply from an unregistered person,

shall, before commencement of such movement, furnish information relating to the said goods as specified in Part A of FORM GST EWB-01, electronically, on the common portal along with such other information as may be required on the common portal and a unique number will be generated on the said portal:

Provided that the transporter, on an authorization received from the registered person, may furnish information in Part A of FORM GST EWB-01, electronically, on the common portal along with such other information as may be required on the common portal and a unique number will be generated on the said portal:

Provided further that where the goods to be transported are supplied through an e-commerce operator or a courier agency, on an authorization received from the consignor, the information in **Part A of FORM GST EWB-01** may be furnished by such e-commerce operator or courier agency and a unique number will be generated on the said portal:

Provided also that where goods are sent by a principal located in one State or Union territory to a job worker located in any other State or Union territory, the e-way bill shall be generated either by the principal or the job worker, if registered, irrespective of the value of the consignment:

Provided also that where handicraft goods are transported from one State or Union territory to another State or Union territory by a person who has been exempted from the requirement of obtaining registration under clauses (i) and (ii) of section 24, the e-way bill shall be generated by the said person irrespective of the value of the consignment.

Explanation 1.—For the purposes of this rule, the expression “handicraft goods” has the meaning as assigned to it in the Government of Uttarakhand Finance section-8, Notification No. 801/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 12th October, 2017 as amended from time to time.

Explanation 2.—For the purposes of this rule, the consignment value of goods shall be the value, determined in accordance with the provisions of section 15, declared in an invoice, a bill of supply or a delivery challan, as the case may be, issued in respect of the said consignment and also includes the central tax, State or Union territory tax, integrated tax and cess charged, if any, in the document and shall exclude the value of exempt supply of goods where the invoice is issued in respect of both exempt and taxable supply of goods.

(2) Where the goods are transported by the registered person as a consignor or the recipient of supply as the consignee, whether in his own conveyance or a hired one or a public conveyance, by road, the said person shall generate the e-way bill in **FORM GST EWB-01** electronically on the common portal after furnishing information in **Part B of FORM GST EWB-01**.

(2A) Where the goods are transported by railways or by air or vessel, the e-way bill shall be generated by the registered person, being the supplier or the recipient, who shall, either before or after the commencement of movement, furnish, on the common portal, the information in **Part B of FORM GST EWB-01**:

Provided that where the goods are transported by railways, the railways shall not deliver the goods unless the e-way bill required under these rules is produced at the time of delivery.

(3) Where the e-way bill is not generated under sub-rule (2) and the goods are handed over to a transporter for transportation by road, the registered person shall furnish the information relating to the transporter on the common portal and the e-way bill shall be generated by the transporter on the said portal on the basis of the information furnished by the registered person in **Part A of FORM GST EWB-01**:

Provided that the registered person or, the transporter may, at his option, generate and carry the e-way bill even if the value of the consignment is less than fifty thousand rupees:

Provided further that where the movement is caused by an unregistered person either in his own conveyance or a hired one or through a transporter, he or the transporter may, at their option, generate the e-way bill in **FORM GST EWB-01** on the common portal in the manner specified in this rule:

Provided also that where the goods are transported for a distance of upto fifty kilometers within the State from the place of business of the consignor to the place of business of the transporter for further transportation, the supplier or the recipient, or as the case maybe, the transporter may not furnish the details of conveyance in **Part B** of **FORM GST EWB-01**.

Explanation 1.—For the purposes of this sub-rule, where the goods are supplied by an unregistered supplier to a recipient who is registered, the movement shall be said to be caused by such recipient if the recipient is known at the time of commencement of the movement of goods.

Explanation 2.—The e-way bill shall not be valid for movement of goods by road unless the information in **Part B** of **FORM GST EWB-01** has been furnished except in the case of movements covered under the third proviso to sub-rule (3) and the proviso to sub-rule (5).

(4) Upon generation of the e-way bill on the common portal, a unique e-way bill number (EBN) shall be made available to the supplier, the recipient and the transporter on the common portal.

(5) Where the goods are transferred from one conveyance to another, the consignor or the recipient, who has provided information in **Part A** of the **FORM GST EWB-01**, or the transporter shall, before such transfer and further movement of goods, update the details of conveyance in the e-way bill on the common portal in **Part B** of **FORM GST EWB-01**:

Provided that where the goods are transported for a distance of up to fifty kilometers within the State from the place of business of the transporter finally to the place of business of the consignee, the details of the conveyance may not be updated in the e-way bill.

(5A) The consignor or the recipient, who has furnished the information in **Part A** of **FORM GST EWB-01**, or the transporter, may assign the e-way bill number to another registered or enrolled transporter for updating the information in **Part B** of **FORM GST EWB-01** for further movement of the consignment:

Provided that after the details of the conveyance have been updated by the transporter in **Part B** of **FORM GST EWB-01**, the consignor or recipient, as the case maybe, who has furnished the information in **Part A** of **FORM GST EWB-01** shall not be allowed to assign the e-way bill number to another transporter.

(6) After e-way bill has been generated in accordance with the provisions of sub-rule (1), where multiple consignments are intended to be transported in one conveyance, the transporter may indicate the serial number of e-way bills generated in respect of each such consignment electronically on the common portal and a consolidated e-way bill in **FORM GST EWB-02** maybe generated by him on the said common portal prior to the movement of goods.

(7) Where the consignor or the consignee has not generated the e-way bill in **FORM**

GST EWB-01 and the aggregate of the consignment value of goods carried in the conveyance is more than fifty thousand rupees, the transporter, except in case of transportation of goods by railways, air and vessel, shall, in respect of inter-State supply, generate the e-way bill in **FORM GSTEWB-01** on the basis of invoice or bill of supply or delivery challan, as the case maybe, and may also generate a consolidated e-way bill in **FORM GST EWB-02** on the common portal prior to the movement of goods:

Provided that where the goods to be transported are supplied through an e-commerce operator or a courier agency, the information in **Part A** of **FORM GST EWB-01** may be furnished by such e-commerce operator or courier agency.

(8) The information furnished in **Part A** of **FORM GST EWB-01** shall be made available to the registered supplier on the common portal who may utilize the same for furnishing the details in **FORM GSTR-1**:

— Provided that when the information has been furnished by an unregistered supplier or an unregistered recipient in **FORM GST EWB-01**, he shall be informed electronically, if the mobile number or the e-mail is available.

(9) Where an e-way bill has been generated under this rule, but goods are either not transported or are not transported as per the details furnished in the e-way bill, the e-way bill may be cancelled electronically on the common portal within twenty four hours of generation of the e-way bill:

Provided that an e-way bill cannot be cancelled if it has been verified in transit in accordance with the provisions of rule 138B:

Provided further that the unique number generated under sub-rule (1) shall be valid for a period of fifteen days for updation of **Part B** of **FORM GST EWB-01**.

(10) An e-way bill or a consolidated e-way bill generated under this rule shall be valid for the period as mentioned in column (3) of the Table below from the relevant date, for the distance, within the country, the goods have to be transported, as mentioned in column (2) of the said Table:-

Sl. No.	Distance	Validity period
(1)	(2)	(3)
1.	Upto 100 km.	One day in cases other than Over Dimensional Cargo
2.	For every 100 km. or part thereof thereafter	One additional day in cases other than Over Dimensional Cargo
3.	Upto 20 km	One day in case of Over Dimensional Cargo
4.	For every 20 km. or part thereof thereafter	One additional day in case of Over Dimensional Cargo:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, extend the validity period of an e-way bill for certain categories of goods as may be specified therein:

Provided further that where, under circumstances of an exceptional nature, including trans-shipment, the goods cannot be transported within the validity period of the e-way bill, the transporter may extend the validity period after updating the details in Part B of FORM GST EWB-01, if required.

Explanation 1.—For the purposes of this rule, the “relevant date” shall mean the date on which the e-way bill has been generated and the period of validity shall be counted from the time at which the e-way bill has been generated and each day shall be counted as the period expiring at midnight of the day immediately following the date of generation of e-way bill.

Explanation 2.— For the purposes of this rule, the expression “Over Dimensional Cargo” shall mean a cargo carried as a single indivisible unit and which exceeds the dimensional limits prescribed in rule 93 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, made under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

(11) The details of the e-way bill generated under this rule shall be made available to the-

(a) supplier, if registered, where the information in Part A of FORM GST EWB-01 has been furnished by the recipient or the transporter; or

(b) recipient, if registered, where the information in Part A of FORM GST EWB-01 has been furnished by the supplier or the transporter,

on the common portal, and the supplier or the recipient, as the case maybe, shall communicate his acceptance or rejection of the consignment covered by the e-way bill.

(12) Where the person to whom the information specified in sub-rule (11) has been made available does not communicate his acceptance or rejection within seventy two hours of the details being made available to him on the common portal, or the time of delivery of goods whichever is earlier, it shall be deemed that he has accepted the said details.

(13) The e-way bill generated under this rule or under rule 138 of the Central Goods and Services Tax Rules or under rule 138 of the Goods and Services Tax Rules of any State or Union territory shall be valid in the State.

(14) Notwithstanding anything contained in this rule, no e-way bill is required to be generated—

(a) where the goods being transported are specified in Annexure;

(b) where the goods are being transported by a non-motorised conveyance;

(c) where the goods are being transported from the customs port, airport, air cargo complex and land customs station to an inland container depot or a container freight station for clearance by Customs;

(d) in respect of movement of such goods and within such areas in the State and for values not exceeding such amount as the Commissioner of State Tax, in consultation with the Principal Chief Commissioner/Chief Commissioner of Central Tax, may, subject to conditions that may be specified, notify;

(e) where the goods, other than de-oiled cake, being transported, are specified in the Schedule appended to Notification No. 518/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29th June, 2017 of Government of Uttarakhand Finance section-8 as amended from time to time;

- (f) where the goods being transported are alcoholic liquor for human consumption, petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas or aviation turbine fuel;
- (g) where the supply of goods being transported is treated as no supply under Schedule III of the Act;
- (h) where the goods are being transported—
- (i) under customs bond from an inland container depot or a container freight station to a customs port, airport, air cargo complex and land customs station, or from one customs station or customs port to another customs station or customs port, or
- (ii) under customs supervision or under customs seal;
- (i) where the goods being transported are transit cargo from or to Nepal or Bhutan;
- (j) where the goods being transported are exempt from tax under Notification No. 519/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29th June, 2017 and Notification No. 842/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 25th October, 2017 of Government of Uttarakhand Finance section-8 as amended from time to time;
- (k) any movement of goods caused by defence formation under Ministry of defence as a consignor or consignee;
- (l) where the consignor of goods is the Central Government, Government of any State or a local authority for transport of goods by rail;
- (m) where empty cargo containers are being transported; and
- (n) where the goods are being transported upto a distance of twenty kilometers from the place of the business of the consignor to a weighbridge for weighment or from the weighbridge back to the place of the business of the said consignor subject to the condition that the movement of goods is accompanied by a delivery challan issued in accordance with rule 55.

Explanation. - The facility of generation, cancellation, updation and assignment of e-way bill shall be made available through SMS to the supplier, recipient and the transporter, as the case may be.

ANNEXURE
[(See rule 138 (14)]

S. No.	Description of Goods
(1)	(2)
1.	Liquefied petroleum gas for supply to household and non domestic exempted category (NDEC) customers
2.	Kerosene oil sold under PDS
3.	Postal baggage transported by Department of Posts
4.	Natural or cultured pearls and precious or semi-precious stones; precious metals and metals clad with precious metal — (Chapter 71)

	Jewellery, goldsmiths' and silversmiths' wares and other	
5.	articles (Chapter 71)	
6.	Currency	
7.	Used personal and household effects	
8.	Coral, unworked (0508) and worked coral (9601)";	

Amendment in 4. For rule 138A of the "Principal Rules", set out in column-1, the **Rule 138A** following rule set out in column-2, shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Hereby substituted rule
<p>138A. Documents and devices to be carried by a person-in-charge of a conveyance.-</p> <p>(1) The person in charge of a conveyance shall carry—</p> <p>(a) the invoice or bill of supply or delivery challan, as the case may be; and</p> <p>(b) a copy of the e-way bill or the e-way bill number, either physically or mapped to a Radio Frequency Identification Device embedded on to the conveyance in such manner as may be notified by the Commissioner.</p>	<p>138A. Documents and devices to be carried by a person-in-charge of a conveyance.-</p> <p>(1) The person in charge of a conveyance shall carry—</p> <p>(a) the invoice or bill of supply or delivery challan, as the case may be; and</p> <p>(b) a copy of the e-way bill in physical form or the e-way bill number in electronic form or mapped to a Radio Frequency Identification Device embedded on to the conveyance in such manner as may be notified by the Commissioner:</p> <p>Provided that nothing contained in clause(b) of this sub-rule shall apply in case of movement of goods by rail or by air or vessel.</p>
<p>(2) A registered person may obtain an Invoice Reference Number from the common portal by uploading, on the said portal, a tax invoice issued by him in FORM GST INV-1 and produce the same for verification by the proper officer in lieu of the tax invoice and such number shall be valid for a period of thirty days from the date of uploading.</p>	<p>(2) A registered person may obtain an Invoice Reference Number from the common portal by uploading, on the said portal, a tax invoice issued by him in FORM GST INV-1 and produce the same for verification by the proper officer in lieu of the tax invoice and such number shall be valid for a period of thirty days from the date of uploading.</p>
<p>(3) Where the registered person uploads the invoice under sub-rule (2), the information in Part A of FORM GST EWB-01 shall be auto-populated by the common portal on the</p>	<p>(3) Where the registered person uploads the invoice under sub-rule (2), the information in Part A of FORM GST EWB-01 shall be auto-populated by the common portal on the basis</p>

<p>basis of the information furnished in FORM GST INV-1.</p> <p>(4) The Commissioner may, by notification, require a class of transporters to obtain a unique Radio Frequency Identification Device and get the said device embedded on to the conveyance and map the e-way bill to the Radio Frequency Identification Device prior to the movement of goods.</p> <p>(5) Notwithstanding anything contained clause (b) of sub-rule (1), where circumstances so warrant, the Commissioner may, by notification, require the person-in-charge of the conveyance to carry the following documents instead of the e-way bill-</p> <p>(a) tax invoice or bill of supply or bill of entry; or</p> <p>(b) a delivery challan, where the goods are transported for reasons other than by way of supply.</p>	<p>of the information furnished in FORM GST INV-1.</p> <p>(4) The Commissioner may, by notification, require a class of transporters to obtain a unique Radio Frequency Identification Device and get the said device embedded on to the conveyance and map the e-way bill to the Radio Frequency Identification Device prior to the movement of goods.</p> <p>(5) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-rule (1), where circumstances so warrant, the Commissioner may, by notification, require the person-in-charge of the conveyance to carry the following documents instead of the e-way bill</p> <p>(a) tax invoice or bill of supply or bill of entry; or</p> <p>(b) a delivery challan, where the goods are transported for reasons other than by way of supply.”;</p>
---	---

Amendment in 5. For rule 138B of the “Principal Rules”, set out in column-1, the **Rule 138B** following rule set out in column-2, shall be substituted, namely:-

Column-1	Column-2
Existing rule	Hereby substituted rule
<p>138B. Verification of documents and conveyances.-</p> <p>(1) The Commissioner or an officer empowered by him in this behalf may authorise the proper officer to intercept any conveyance to verify the e-way bill or the e-way bill number in physical form for all inter-State and intra-State movement of goods.</p> <p>(2) The Commissioner shall get Radio Frequency Identification Device readers installed at places where the verification of movement of goods is required to be carried out and verification of movement of vehicles shall be done through such device</p>	<p>138B. Verification of documents and conveyances.-</p> <p>(1) The Commissioner or an officer empowered by him in this behalf may authorize the proper officer to intercept any conveyance to verify the e-way bill in physical or electronic form for all inter-State and intra-State movement of goods.</p> <p>(2) The Commissioner shall get Radio Frequency Identification Device readers installed at places where the verification of movement of goods is required to be carried out and verification of movement of vehicles shall be done through such device readers</p>

readers where the e-way bill has been mapped with the said device.	where the e-way bill has been mapped with the said device.
(3) The physical verification of conveyances shall be carried out by the proper officer as authorised by the Commissioner or an officer empowered by him in this behalf: Provided that on receipt of specific information on evasion of tax, physical verification of a specific conveyance can also be carried out by any officer after obtaining necessary approval of the Commissioner or an officer authorised by him in this behalf.	(3) The physical verification of conveyances shall be carried out by the proper officer as authorised by the Commissioner or an officer empowered by him in this behalf: Provided that on receipt of specific information on evasion of tax, physical verification of a specific conveyance can also be carried out by any other officer after obtaining necessary approval of the Commissioner or an officer authorised by him in this behalf.”

Amendment in 6. For rule 138C of the “Principal Rules”, set out in column-1, the **Rule 138C** following rule set out in column-2, shall be substituted, namely:-

Column-1	Column-2
Existing rule	Hereby substituted rule
138C. Inspection and verification of goods.- (1) A summary report of every inspection of goods in transit shall be recorded online by the proper officer in Part A of FORM GST EWB-03 within twenty four hours of inspection and the final report in Part B of FORM GST EWB-03 shall be recorded within three days of such inspection.	138C. Inspection and verification of goods.- (1) A summary report of every inspection of goods in transit shall be recorded online by the proper officer in Part A of FORM GST EWB-03 within twenty four hours of inspection and the final report in Part B of FORM GST EWB-03 shall be recorded within three days of such inspection.
(2) Where the physical verification of goods being transported on any conveyance has been done during transit at one place within the State or in any other State, no further physical verification of the said conveyance shall be carried out again in the State, unless a specific information relating to evasion of tax is made available subsequently.	(2) Where the physical verification of goods being transported on any conveyance has been done during transit at one place within the State or in any other State or Union territory, no further physical verification of the said conveyance shall be carried out again in the State, unless a specific information relating to evasion of tax is made available subsequently.”;

Amendment in 7. For rule 138D of the “Principal Rules”, set out in column-1, the **Rule 138D** following rule set out in column-2, shall be substituted, namely:-

Column-1	Column-2
Existing rule	Hereby substituted rule
13-8D. Facility for uploading information regarding detention of vehicle.- Where a vehicle has been intercepted and detained for a period exceeding thirty minutes, the transporter may upload the said information in FORM GST EWB-04 on the common portal.	138D. Facility for uploading information regarding detention of vehicle- Where a vehicle has been intercepted and detained for a period exceeding thirty minutes, the transporter may upload the said information in FORM GST EWB-04 on the common portal.”;

**Amendment in
Forms**

8. For FORM GST EWB-01, FORM GST EWB-02, FORM GST EWB-03, FORM GST EWB-04 and FORM GST INV-1 of the “Principal Rules”, the following Forms, shall be substituted, namely:-

“FORM GST EWB-01

(See rule 138)

E-Way Bill

E-Way Bill No.

E-Way Bill date

Generator

Valid from

Valid until

PART-A	
A.1	GSTIN of Supplier
A.2	Place of Dispatch
A.3	GSTIN of Recipient
A.4	Place of Delivery
A.5	Document Number
A.6	Document Date
A.7	Value of Goods
A.8	HSN Code
A.9	Reason for Transportation
PART-B	
B.1	Vehicle Number for Road
B.2	Transport

	Document Number/Defence Vehicle No./ Temporary Vehicle Registration No./Nepal or Bhutan Vehicle Registration No.	
--	--	--

Notes:

1. HSN Code in column A.8 shall be indicated at minimum two digit level for taxpayers having annual turnover upto five crore rupees in the preceding financial year and at four digit level for taxpayers having annual turnover above five crore rupees in the preceding financial year.
2. Document Number may be of Tax Invoice, Bill of Supply, Delivery Challan or Bill of Entry.
3. Transport Document number indicates Goods Receipt Number or Railway Receipt Number or Forwarding Note number or Parcel way bill number issued by railways or Airway Bill Number or Bill of Lading Number.
4. Place of Delivery shall indicate the PIN Code of place of delivery.
5. Place of dispatch shall indicate the PIN Code of place of dispatch.
6. Where the supplier or the recipient is not registered, then the letters "URP" are to be filled-in in column A.1 or, as the case may be, A.3.
7. Reason for Transportation shall be chosen from one of the following:-

Code	Description
1	Supply
2	Export or Import
3	Job Work
4	SKD or CKD
5	Recipient not known
6	Line Sales
7	Sales Return
8	Exhibition or fairs
9	For own use
10	Others

FORM GST EWB-02

(See rule 138)

Consolidated E-Way Bill**Consolidated E-Way Bill No.** :**Consolidated E-Way Bill Date** :**Generator** :**Vehicle Number** :

Number of E-Way		
Bills		
E-Way Bill Number		

FORM GST EWB-03

(See rule 138C)

Verification Report

Part A	
Name of the Officer	
Place of inspection	
Time of inspection	
Vehicle Number	
E-Way Bill Number	
Tax Invoice or Bill of Supply or Delivery	
Challan or Bill of Entry date	
Tax Invoice or Bill of Supply or Delivery	
Challan or Bill of Entry Number	
Name of person in-charge of vehicle	
Description of goods	
Declared quantity of goods	

Declared value of goods	
Brief description of the discrepancy	
Whether goods were detained?	
If not, date and time of release of vehicle	
Part B	
Actual quantity of goods	
Actual value of the Goods	
Tax payable	
Integrated tax	
Central tax	
State tax	
Cess	
Penalty payable	
Integrated tax	
Central tax	
State tax	
Cess	
Details of Notice	
Date	
Number	
Summary of findings	

FORM GST EWB-04

(See rule 138D)

Report of detention

E-Way Bill Number	
Approximate Location of detention	
Period of detention	
Name of Officer in-charge	(if known)
Date	
Time	

FORM GST INV - 1

(See rule 138A)

Generation of Invoice Reference Number

IRN:		Date:	
Details of Supplier			
GSTIN			
Legal Name			
Trade name, if any			
Address			
Serial No. of Invoice			
Date of Invoice			
	Details of Recipient (Billed to)	Details of Consignee (Shipped to)	
GSTIN or UIN, if available			
Name			
Address			
State (name and code)			

Column-1	Column-2
Existing	Hereby substituted
DECLARATION [second proviso to section 54(3)]	“DECLARATION [second proviso to section 54(3)]
I hereby declare that the goods exported are not subject to any export duty. I also declare that I have not availed any drawback on goods or services or both and that I have not claimed refund of the integrated tax paid on supplies in respect of which refund is claimed.	I hereby declare that the goods exported are not subject to any export duty. I also declare that I have not availed any drawback of central excise duty/service tax/central tax on goods or services or both and that I have not claimed refund of the integrated tax paid on supplies in respect of which refund is claimed.
Signature _____	Signature _____
Name – _____	Name – _____
Designation / Status _____	Designation / Status”;

Amendment in 10. With effect from the 07th day of March, 2018, in FORM GST FORM GST RFD-01A of the “Principal Rules”, for the RFD-01A DECLARATION [second proviso to section 54(3)], the following DECLARATION shall be substituted, namely:-

Column-1	Column-2
Existing	Hereby substituted
DECLARATION [second proviso to section 54(3)]	DECLARATION [second proviso to section 54(3)]
I hereby declare that the goods exported are not subject to any export duty. I also declare that I have not availed any drawback on goods or services or both and that I have not claimed refund of the integrated tax paid on supplies in respect of which refund is claimed.	I hereby declare that the goods exported are not subject to any export duty. I also declare that I have not availed any drawback of central excise duty/service tax/central tax on goods or services or both and that I have not claimed refund of the integrated tax paid on supplies in respect of which refund is claimed.
Signature _____	Signature _____
Name – _____	Name – _____
Designation / Status _____	Designation / Status”.

By Order,

RADHA RATURI,

Principal Secretary.

आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड

(राज्य कर विभाग)

अधिसूचना

23 मार्च, 2018 ई०

संख्या 6237(i)/सी०एस०टी०यू०के०/जी०एस०टी०-विधि/2017-18-उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) सपठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 168 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आयुक्त, एतद्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, विनिर्दिष्ट करती हूँ कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्ररूप जीएसटीआर-3ब में उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट अन्तिम तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात्:-

सारणी

क्रम संख्या	मास	प्ररूप जीएसटीआर-3ब में विवरणी फाइल करने के लिए अन्तिम तारीख
1.	अप्रैल, 2018	20 मई, 2018
2.	मई, 2018	20 जून, 2018
3.	जून, 2018	20 जुलाई, 2018

2. प्ररूप जीएसटीआर-3ब के अनुसार कर दायित्व का निर्वहन करने के लिए करों का संदाय-प्ररूप जीएसटीआर-3ब में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का उन्मोचन उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथा उल्लिखित अन्तिम तारीख, जिस तक उससे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, से पूर्व यथास्थिति इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही या इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही से विकलित करके करेगा।

सौजन्या,

आयुक्त राज्य कर,

उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

March 23, 2018

No. 6237(i)/CSTUK/GST-Vidhi Section/2017-18-In exercise of the powers conferred by section 168 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, I, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** for the month as specified in column (2) of the Table below shall be furnished electronically through the common portal, on or before the last date as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Month	Last date for filing of return in FORM GSTR-3B
1.	April, 2018	20 th May, 2018
2.	May, 2018	20 th June, 2018
3.	June, 2018	20 th July, 2018

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B**--Every registered person furnishing the return in FORM GSTR-3B shall, subject to the provisions of section 49 of the Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as mentioned in column (3) of the said Table, on which he is required to furnish the said return.

SOWJANYA,

Commissioner, State Tax,

Uttarakhand.

विपिन चन्द्र,

एडिशनल कमिशनर, राज्य कर,

मुख्यालय, देहरादून।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 अप्रैल, 2018 ई0 (चैत्र 24, 1940 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
कार्यालय नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा
पालतू कुत्ता लाइसेन्स उपनियमावली

09 मार्च, 2018 ई0

पत्र संख्या 2037/30-1 उपनियमावली/2017-18-नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा द्वारा अंगीकृत उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(1) (ज) का (झ) के द्वारा प्रचलित नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा की मासिक अधिवेशन दिनांक 01.02.2018 के प्रस्ताव सं0 04 द्वारा पालतू कुत्तों का लाइसेन्स बनाने का निर्णय लिया गया है। नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 300(1) के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव हेतु समाचार-पत्र में प्रकाशित किया गया था। जिस पर समयान्तर्गत कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए है। उपरोक्त उप नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

उपनियमावली

1. संक्षिप्त नाम-यह उपनियमावली नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा, पालतू कुत्तों का लाइसेन्स उपनियमावली, 2017 कहलायेगी।
2. विस्तार/प्रसार-इस नियमावली का विस्तार नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में लागू होगा।

परिभाषाएँ

- (1) नगरपालिका परिषद का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा से है।
- (2) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा से है।

- (3) अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा से है।
- (4) यह उपनियमावली नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा कहलायेगी और नगरपालिका अधिनियम, 1916 अधिनियम सं0 (2) उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण अध्यादेश 2002 से है।
- (5) पालिका परिषद्, अल्मोड़ा में ₹ 200.00 (दो सौ मात्र) जमा कर लाइसेन्स प्राप्त करना होगा। पालतू कुत्तों को पालने वाले व्यक्ति को अधिशासी अधिकारी के नाम प्रार्थना-पत्र पर पशुचिकित्सालय से टीकाकरण की प्रति भी संलग्न करनी होगी।
- (6) यदि कोई व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते का लाइसेन्स नहीं बनाता है तो उसे प्रतिवर्ष ₹ 1000.00 (एक हजार) की दर से दण्ड देय होगा साथ ही सार्वजनिक मार्ग में कुत्तों को शौच कराने पर ₹ 250.00 (दो सौ पचास मात्र) से लेकर ₹ 2000.00 (दो हजार) तक दण्ड किया जा सकता है।

शास्ति

नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा इस विधि के किसी भी उल्लंघन पर ₹ 1,000.00 (एक हजार) तक दण्ड किया जा सकेगा। यदि उल्लंघन जारी रहा तो अतिरिक्त दण्ड ₹ 100.00 (एक सौ रुपया) प्रतिदिन की दर से वसूल किया जा सकेगा। जो प्रथम दोष/निर्णय की तिथि से जब तक अपराधी अपराध करता है तो दण्ड किया जायेगा।

संशोधित अचल सम्पत्ति दाखिल खारिज उपनियमावली

09 मार्च, 2018 ई०

पत्र संख्या 2038/30-1 उपनियमावली/2017-18-नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा अंगीकृत उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(1) द्वारा प्रचलित नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा की मासिक बैठक दिनांक 18.11.2017 के प्रस्ताव सं० 15(1) द्वारा अचल सम्पत्ति दाखिल खारिज उपनियमावली के दाखिल खारिज हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ शुल्क को संशोधित किए जाने का निर्णय लिया गया है, इसके अतिरिक्त अन्य नियम व शर्त यथावत् रहेगी। नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 300(1) के अन्तर्गत आपत्ति/सुझाव हेतु समाचार-पत्र में प्रकाशित किया गया था, जिस पर समयान्तर्गत कोई आपत्ति व सुझाव प्राप्त नहीं हुए है। उपरोक्त उपनियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

संशोधित उपनियमावली

नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा पूर्व में प्रकाशित अचल सम्पत्ति के दाखिल खारिज उपनियमावली कार्यालय पत्रांक 628/30-1/2009-10/दिनांक 01 सितम्बर, 2009 के प्रस्ताव सं० 15(1) मासिक बैठक दिनांक 18.11.2017 द्वारा अनुसूची शुल्क दाखिल खारिज हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ शुल्क ₹ 750.00 (सात सौ पचास) को संशोधित किया गया, जो संशोधित कर ₹ 1,500.00 (एक हजार पाँच सौ) निर्धारित किया गया है।

शास्ति

यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा तो वह वैधानिक दण्ड का भागी होगा। जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 के अन्तर्गत ₹ 1,000.00 (एक हजार रुपया मात्र) अर्थदण्ड तक होगा। यदि उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त दण्ड ₹ 100.00 (एक सौ रुपया मात्र) प्रतिदिन होगा।

श्याम सुन्दर प्रसाद,

अधिसासी अधिकारी,

नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा।

प्रकाश चन्द्र जोशी,

अध्यक्ष,

नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा।